



नवा रायपुर बन रहा देश का नया टेक्नोलॉजी हब

छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनेंगे AI, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग

छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्र नवा रायपुर अब तेजी से देश के उभरते टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योगों के अनुकूल नीतियां और तेज प्रशासनिक प्रक्रियाओं ने इस क्षेत्र को हाईटेक निवेश का नया गढ़ बना दिया है। अब नवा रायपुर केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीतियों और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहनों के कारण देश-विदेश की कई बड़ी कंपनियां छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित हो रही हैं। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप, एआई आधारित तकनीक, टेलीकॉम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उद्योगों के लिए यहां मजबूत संभावनाएं तैयार हुई हैं।



“हम अब इंटरनेट की 6G और 7G तकनीक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है, कि इसके लिए माइक्रोचिप हमारे देश में ही तैयार होंगे और नवा रायपुर अटल नगर में हमारे इंजीनियर और विशेषज्ञ इसे आकार देंगे।

– विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



नवा रायपुर में तैयार होगा भविष्य का डिजिटल भारत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाल ही में नवा रायपुर में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ अब तकनीकी क्रांति के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश में उपयोग होने वाली अत्याधुनिक संचार तकनीकों के लिए आवश्यक चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अब भारत में ही तैयार किए जाएंगे और इसमें नवा रायपुर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में विकसित छत्तीसगढ़ की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। तकनीक, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व के विकसित देशों ने तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता देकर ही आर्थिक शक्ति हासिल की है और अब छत्तीसगढ़ भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।



देश का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

नवा रायपुर अटल नगर में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) आकार ले रहा है। यह विशेष क्षेत्र पूरी तरह से AI और कंप्यूटर डेटा से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों के विकास, संचालन और नवाचार को समर्पित होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को रैकबैक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह स्थायी लगभग 6 एकड़ भूमि में फैला होगा और इसमें 1.5 लाख वर्ग फुट का एक विशाल और अत्याधुनिक डेटा सेंटर शामिल होगा। आगे की योजना में चार और हाई-डेंसिटी डेटा सेंटरों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी संयुक्त क्षमता 80 मेगावाट होगी। यह क्षमता देश के कई राज्यों के डिजिटल नेटवर्क को सुचारु रूप से संचालित करने में सक्षम होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस परियोजना को 'नवा छत्तीसगढ़ की नई शुरुआत' बताया। उन्होंने कहा कि यह निवेश राज्य के युवाओं को नए रोजगार के अवसर देगा और छत्तीसगढ़ को एक तकनीकी पहचान प्रदान करेगा। यह पहल डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को भी मजबूती देगी।



हाईटेक प्लांट्स से युवाओं को मिलेगा बड़ा अवसर

नवा रायपुर में विकसित हो रहे इन आधुनिक उद्योगों से प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावनाएं बनी हैं। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एआई, ऑटोमेशन और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में नवा रायपुर देश के प्रमुख टेक्निकल टैलेंट हब के रूप में उभर सकता है। यहां बनने वाले हाईटेक प्लांट्स से स्थानीय युवाओं को देश छोड़कर बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी और उन्हें अपने ही राज्य में आधुनिक तकनीकी उद्योगों में काम करने का अवसर मिलेगा।



ईवी व पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार नवा रायपुर में प्रस्तावित नई परियोजनाएं केवल चिप निर्माण तक सीमित नहीं रहेंगी। यहां पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांजिस्टर, ईवी टेक्नोलॉजी, स्मार्ट डिवाइस और भविष्य की संचार तकनीकों से जुड़े बड़े उत्पादन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में सहायक उद्योगों, स्टार्टअप्स और रिसर्च आधारित कंपनियों के लिए भी बड़े अवसर तैयार होंगे। इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और हजारों छोटे व्यवसायों को भी लाभ मिलेगा।



सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने दूसरे विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को मंजूरी

नवा रायपुर अटल नगर में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा दूसरे विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को मंजूरी दी गई है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग आधारित SEZ 10.13 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित होगा और इसमें राज्य का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र लगाया जाएगा। इस स्वर्ण को 'पोलिमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' को विकसित करने के लिए मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से नवा रायपुर में हाईटेक उद्योगों के लिए एक नया केंद्र विकसित होगा, जिससे लगभग 1,300 स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह कदम राज्य में हाई-टेक मैनुफैक्चरिंग को आकर्षित करने और तकनीकी भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

तेज प्रशासनिक फैसलों ने बढ़ाया निवेशकों का भरोसा

राज्य सरकार और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उद्योगों को तेजी से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। निवेशकों को कम समय में भूमि, बिजली,

कनेक्टिविटी और अन्य आवश्यक स्वीकृतियां मिलने से कंपनियों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ केवल खनिज

और इस्पात उद्योगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक तकनीकी उद्योगों का भी नया केंद्र बनकर उभर रहा है।

नवा रायपुर के सेक्टर-5 में डेढ़ लाख वर्ग फीट जमीन पर प्लांट



सीएम साय ने बताया कि पिछले साल दिसंबर में आयोजित एक इवेस्टर्स मीट में राज्य के अधिकारियों की मुलाकात पोलिमेटेक के प्रबंधन से हुई थी, उस दौरान कंपनी ने छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई थी। जिसके बाद उद्योग विभाग और एनआरडीए ने 45 दिनों के अंदर नवा रायपुर के सेक्टर-5 में डेढ़ लाख वर्ग फीट भूमि उपलब्ध कराई।



शिक्षा संस्थानों के साथ बढ़ रहा उद्योगों का जुड़ाव

नवा रायपुर स्थित तकनीकी संस्थान और इंजीनियरिंग कॉलेज अब उद्योगों के साथ मिलकर नई रिसर्च और इनोवेशन गतिविधियों पर कार्य कर रहे हैं। माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, चिप डिजाइन, क्रांति डिवाइस और एआई आधारित सिस्टम पर लगातार संगोष्ठियां और रिसर्च प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच बढ़ता सहयोग आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन केंद्रों में शामिल कर सकता है। इससे छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ उद्योगों में सीधे काम करने और नई तकनीकों पर शोध करने का अवसर मिलेगा।



'मेक इन सिलिकॉन' की ओर छत्तीसगढ़

नवा रायपुर में आयोजित तकनीकी संगोष्ठियों और इंडस्ट्री कॉन्वेल्व में अब 'मेक इन सिलिकॉन' जैसे विजन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण को मजबूत करना और आत्मनिर्भर तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इसी गति से निवेश और तकनीकी विकास जारी रहा, तो आने वाले समय में नवा रायपुर देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्रों में शामिल हो सकता है। इससे छत्तीसगढ़ की पहचान एक पारंपरिक औद्योगिक राज्य से बदलकर आधुनिक तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित होगी।



छत्तीसगढ़ का नया सपना- टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता

छत्तीसगढ़ अब केवल प्राकृतिक संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि तकनीकी नवाचार और आधुनिक उद्योगों के लिए भी जाना जाएगा। नवा रायपुर में तेजी से विकसित हो रहा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम राज्य के लिए एक नई आर्थिक क्रांति का आधार बन रहा है। सरकार, उद्योग और शिक्षा संस्थानों के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ अब देश के डिजिटल और तकनीकी भविष्य में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। आने वाले वर्षों में नवा रायपुर का नाम देश की नई 'सिलिकॉन वैली' के रूप में लिया जाए, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।



6जी और 7जी माइक्रोचिप्स अब यहीं बनेंगे

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में सेमीकंडक्टर उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से कंपनी को यहां निवेश में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि विश्व के जो भी देश विकसित हुए हैं, उन्होंने तकनीक के क्षेत्र में मेहनत की है, अनुसंधान किया है और ऐसा वातावरण बनाया है जिससे तेजी से तकनीकी प्रगति संभव हो पाई। अब 6जी और 7जी तकनीक भी आ रही है और मुझे खुशी है कि इनके लिए आवश्यक माइक्रोचिप्स हमारे देश में ही तैयार होंगे, और नवा रायपुर, अटल नगर में हमारे इंजीनियर इन्हें बनाएंगे।

मुख्य लाभ

- ✓ हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर
- ✓ हाईटेक और आधुनिक तकनीक का विकास
- ✓ स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
- ✓ राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा
- ✓ भारत को तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

नवा रायपुर : भविष्य की तकनीक का मजबूत आधार

आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी, तेज प्रशासनिक प्रक्रियाओं और उद्योगों के अनुकूल नीतियों के कारण नवा रायपुर अब देश के उपर टेक्नोलॉजी शहरों में तेजी से शामिल हो रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को आने वाले वर्षों में देश का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग हब बनाना है।



सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप निर्माण



पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी टेक्नोलॉजी



एआई और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में अग्रणी



हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

संबाद-48873/1



संक्षिप्त समाचार

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का रायपुर दौरा
सुरक्षा को लेकर पुलिस ने किया मॉकड्रिल

रायपुर। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन बुधवार को राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। वे एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रायपुर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, उपराष्ट्रपति सुबह करीब 10 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद 10.45 बजे एम्स रायपुर पहुंचेंगे, जहां सुबह 11 बजे से तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोपहर 12.30 बजे एम्स से रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। इसके बाद दोपहर 1.30 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए रायपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एयरपोर्ट से एम्स तक के रूट पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर रिहर्सल और मॉकड्रिल की जा रही है। पुलिस अधिकारियों और जवानों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दौरे से पहले सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और प्रोटोकॉल समेत अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा चुकी है। पिछले दिनों मुख्य सचिव विकास शील ने मंगलय में उच्च स्तरीय बैठक लेकर उपराष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की थी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए थे।

चर्चाओं के बीच अब दिल्ली में भाजपा प्रदेश
अध्यक्ष किरण देव से मिले तोखन साहू

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा में नए अध्यक्ष की चुनौती का सामना करते हुए प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बताया कि वह नाराज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह नाराज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह नाराज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह नाराज नहीं हैं।

नियुक्ति की चर्चा हर प्लेटफॉर्म पर इतनी होने लगी कि भाजपा मीडिया विभाग को यह कहना पड़ गया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव पार्टी में नहीं आया है। जो भी चर्चा हो रही है वह निराधार है उसका कहीं कोई आधार नहीं है। बावजूद इसके संकेतों के साथ चट रहे राजनीतिक घटनाक्रमों ने बदलाव की चर्चा को चर्चा में बनाए रखा है। जैसे कल भाजपा कार्यालय में किसान मोर्चा की बैठक थी। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक के बाद जब पत्रकारों ने उनका कुशलक्षेम जाना और स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दी। नएस्थान तलाशें माँ दंतेक्षरी से प्रार्थना है कि किरण सिंह देव जी को शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ करें तथा उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करें।

रायपुर-बलौदाबाजार हाईवे पर ट्रक से भिड़ी
क्रेटा, हादसे में रायक की मौत, 3 घायल

रायपुर। रायपुर-बलौदाबाजार मुख्य मार्ग पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। खरोरा थाना क्षेत्र के मंगोली चौक के पास ट्रक और क्रेटा कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।हादसे में क्रेटा सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम शिवम साहू बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक क्रेटा कार क्रमांक सीजी 04 क्यूएफ 6732 में ओमप्रकाश साहू, संजय साहू, शिवम साहू और रामेश्वर कंवेट सवार थे। सभी भटगांव से रायपुर की ओर जा रहे थे। मंगलवार सुबह मंगोली चौक के पास उनकी कार की ट्रक क्रमांक यूपी 32 जेएन 2667 से जोरदार भिड़ंत हो गई।टक्कर इतनी तेज थी कि क्रेटा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार चारों लोगों को चोटें आईं। शिवम साहू की हालत गंभीर बताई गई। बाद में उसकी मौत होने की सूचना मिली। हादसे की सूचना मिलने के बाद डीपीसीआर कंट्रोल रायपुर से खरोरा पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए श्रीकृष्णा अस्पताल, खरोरा भेजा। पुलिस ने घटनास्थल पर यातायात व्यवस्था भी संभाली।

छत्तीसगढ़ में लक्ष्य का 98 प्रतिशत बोनी पूर्ण

रायपुर। प्रदेश में खेती किसानों का कार्य जोरों पर है। राज्य में 01 सितंबर की स्थिति में राज्य के 47.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में लक्ष्य का 98 प्रतिशत बोनी पूर्ण हो चुकी है। इस खरीफ सीजन में 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों को खेती-किसानी में सहूलियतें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने संबंधित अधिकारियों निर्देशित किए गए हैं। उन्होंने किसानों को उनकी मांगों के अनुसार सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण करने को कहा हैं। खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं।

मंत्री केदार कश्यप ने गिनाई ढाई साल की विभागीय उपलब्धियां

रायपुर। वन, जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार के ढाई साल की विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में आदिम संस्कृति, सांस्कृतिक जैव-विविधता के संरक्षण के साथ-साथ हरित विकास और ग्रामीण कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जा रही है।

मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बस्तर की आदिम संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए 572 देवगुड़ियों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का काम किया गया है। इस कार्य पर ढाई वर्षों में 19 करोड़ 5 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को

मिली गति- हरित छत्तीसगढ़ की दिशा में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण और वितरण किया गया। मंत्री के मुताबिक वर्ष 2024 में निर्धारित लक्ष्य से एक करोड़ अधिक 3 करोड़ 50 लाख पौधों का रोपण एवं वितरण हुआ। वर्ष 2025 में लक्ष्य के मुकाबले 215 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करते हुए 3 करोड़ 55 लाख पौधे रोपे और वितरित किए गए। वहीं वर्ष 2026 के अभियान में अब तक 2 करोड़ 23 लाख से अधिक पौधों का रोपण एवं वितरण किया जा चुका है।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को कई योजनाओं का लाभ- मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्रहण का मूल्य 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा है, जिसे देश में सर्वाधिक बताया गया। इसके अलावा 7



लाख 14 हजार संग्राहकों को 153 करोड़ रुपये प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया गया है। महिला मुखिया संग्राहकों को 12 लाख 40 हजार जोड़ी चरण पादुका वितरित की गई, जबकि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई।

36 हजार क्रिंटल से ज्यादा वनोपज

वन्यजीव तस्करी पर सीबीआई करेगी जांच : कश्यप

■ कांग्रेस ने कहा - वन विभाग की लापरवाही से बढ़ी वन्य जीवों की तस्करी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वन्यजीव तस्करी मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में सामने आए वन्यजीव तस्करी के मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग की ओर से जांच सीबीआई को सौंपने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

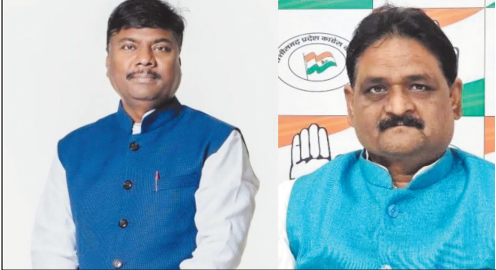
मामला इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीव तस्करी से जुड़ा है, जहां कार्वाइयों के दौरान तस्करी की गिरफ्तारी की गई थी। प्रारंभिक जांच में इस पूरे नेटवर्क के तार दूसरे राज्यों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि तस्करी में अलग-अलग राज्यों के गिरोह सक्रिय हो सकते हैं।

वहीं वन मंत्री केदार कश्यप के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद वन्य जीवों की तस्करी बढ़ गई है। संरक्षित वन्य प्राणी

की खरीदी- वन मंत्री ने बताया, वनोपज के क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर 36,580 क्रिंटल वनोपज की खरीदी की गई। इसके एवज में संग्राहकों को 16 करोड़ 66 लाख रुपये का भुगतान किया गया। वहीं वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से 181 हर्बल उत्पाद तैयार किए गए हैं, जिनका मूल्य 4 करोड़ 42 लाख रुपये बताया गया है।

35 बाघ और 355 हाथियों के संरक्षण पर फोकस- वन्यजीव संरक्षण को लेकर भी विभाग ने विशेष कार्ययोजना तैयार की है। मंत्री ने बताया कि राज्य में 35 बाघों और 355 हाथियों के संरक्षण के लिए विशेष कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है। वन्यजीवों के संरक्षण के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने पर भी विभाग का जोर है।

425 नए गांवों तक पहुंची बस सेवा- मंत्री कश्यप ने बताया, परिवहन क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 425 नए गांवों तक बस सेवा शुरू की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होने का दावा किया गया है। परिवहन विभाग की सेवाओं को डिजिटल किया गया है। इसके तहत ऋष्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की होम डिलीवरी शुरू की गई है। ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार से लोगों को परिवहन कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी संस्कृति के संवर्धन, वन आधारित आजीविका को मजबूत करने और गांवों तक बेहतर परिवहन सुविधाएं पहुंचाने के साथ छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को गति देना है।



शिकार हो रहे हैं। यह राज्य सरकार की उदासीनता और वन विभाग की गंभीर लापरवाही है।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई गिरफ्तारियों के बाद वन विभाग की जांच में तस्करी के बड़े नेटवर्क की आशंका सामने आई है। अधिकारियों को संदेह है कि यह केवल स्थानीय स्तर पर संचालित गिरोह नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से जुड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। इसी को देखते हुए मामले की गहराई से जांच और पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए सीबीआई जांच की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।

वनमंत्री केदार कश्यप के बयान के बाद वन विभाग ने मामले को सीबीआई को सौंपने

के लिए प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीबीआई जांच होने पर वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क, आरोपियों के संपर्क, संभावित अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन और तस्करी के पूरे चैनल की पड़ताल की जा सकेगी। फिलहाल वन विभाग की कार्रवाई और प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। सीबीआई को जांच सौंप जाने के बाद इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।

वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि सरकार अपनी गलतियों का पल्ला झाड़ने के लिए सीबीआई जांच की बात कर रही है। सीबीआई तो केवल संबंधित मामलों की जांच करेगी, लेकिन हमारा जंगल जो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। उसे संरक्षित करने के लिए वन अमले को अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। सीबीआई आकर हमारे वन्य जीवों की रक्षा तो नहीं करेगी। हमारे राज्य के वन मंत्री को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये ही समझ नहीं आ रहा है।

सीजीपीएससी घोटाला : भूपेश बघेल के पीए के ठिकानों पर ईडी की छापेरी

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर छापेरी की। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पर्सनल असिस्टेंट के के चंद्राकर का ठिकाना भी शामिल था। यह छापेरी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई। 2020 और 2021 की सीजीपीएससी परीक्षाओं में ऊँचे ओहदे वाले अधिकारियों और जाने-माने नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने के लिए कथित तौर पर हेर-फेर की गई थी।

ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच, इस मामले में 2024 में दर्ज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) के एक केस से जुड़ी है। एफआईआर में कॉन्ग्रेस नेताओं से जुड़े कई उम्मीदवारों के नाम तो थे, लेकिन नेताओं के नाम नहीं थे। इसमें कहा गया था कि सीजीपीएससी की मेरिट लिस्ट में सीरियल नंबर 1 से 171 तक आने वाले लोग कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों, नेताओं और प्रभावशाली लोगों से जुड़े थे।

राज्य सरकार ने 16 फरवरी, 2024 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी; यह कदम दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किए जाने के लगभग दो महीने बाद उठाया गया था।



सीबीआई ने इस मामले में सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन तमन सिंह सोनवानी, सीजीपीएससी के पूर्व सेक्रेटरी जीवन किशोर ध्रुव, छत्तीसगढ़ सरकार के अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और संबंधित राजनेताओं व अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। हाल ही में, 25 जुलाई को ईडी ने सोनवानी को प्रिंशवॉन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया। ईडी की जांच से पता चला कि सीजीपीएससी के चेयरमैन के तौर पर काम करते हुए, तमन सिंह सोनवानी ने दूसरे सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची। इस साजिश का मकसद गैर-कानूनी तरीके से पैसे लेकर या फायदा उठाकर प्रश्न-पत्र लीक करना और सिलेक्शन प्रोसेस में हेर-फेर करना था, ताकि उनके अपने रिश्तेदारों और पर्सदीदा उम्मीदवारों को डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसे सीनियर सरकारी

पदों पर गलत तरीके से चुना जा सके। ईडी ने 27 जुलाई को एक बयान में कहा, जांच में यह भी पता चला कि 2021 में सीजीपीएससी के भर्ती नियमों में बदलाव करके परिवार की परिभाषा से भतीजे शब्द को हटा दिया गया था, जिससे तमन सिंह सोनवानी के रिश्तेदारों के सिलेक्शन में आसानी हो गई।

सीजीपीएससी घोटाला : आरती वासनिक को मिली जमानत

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के कथित घोटाले से जुड़े मामले में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार (1 सितंबर) को उन्हें नियमित जमानत देने का आदेश दिया है। आरती वासनिक के साथ तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक ललित गनवरी को भी नियमित जमानत दी गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने की। तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक की ओर से सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश और एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरती वासनिक की ओर से बताया गया कि वह एक साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वहीं, मुकदमे में 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं।

विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता : राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की बैठक लेकर विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की संख्या, रिक्त पदों की पूर्ति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन तथा नवाचार एवं स्टार्टअप गतिविधियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को विस्तृत समीक्षा की।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में सीटों के अनुपात में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और इस दिशा में प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में जहां भी व्यवस्थागत कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाए तथा शैक्षणिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के



अनुरूप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री डेका ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी लेते हुए उन्हें शीघ्र भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में नियमानुसार स्थानीय योग्य एवं प्रतिभाशाली लोगों को प्राथमिकता देने के प्रयास किए जाएं, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर मिल सके। श्री डेका ने विश्वविद्यालयों की नैक एवं एनआईआरएफ रैंकिंग की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपनी रैंकिंग में सुधार के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करें।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को अपने आसपास के गांवों को गोद लेकर

वहां इन्वेषन एवं स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में उपलब्ध ज्ञान, विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए। विद्यार्थियों को स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार एवं उद्यमिता से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने ‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत’ संकल्प अभियान में युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने तथा विद्यार्थियों को खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में इंटरनल ऑडिट अनिवार्य रूप से कराने तथा इसके लिए इंटरनल कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं लोक-फ्रूफ बनाने पर विशेष जोर देते हुए इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा नियंत्रकों की आधिकारिक नियुक्ति सुनिश्चित करने कहा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और वे बहुत जल्द पूरी सक्रियता के साथ सीधे कार्यकर्ताओं के बीच लौटेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि अस्वस्थ होने के बावजूद वे संगठन के कामकाज से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और लगातार डिजिटल माध्यमों से पार्टी की सभी गतिविधियों का संचालन व मार्गदर्शन कर रहे हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव प्रदेश कार्यलय में आयोजित होने वाली तमाम महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकों में नियमित रूप से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरक रही, वहीं उनके आगामी अभियानों की रूपरेखा तय करने और कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए वे पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं। श्री देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को भी सुना और देशहित में किए जा रहे अभूतपूर्व प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार

व्यक्त किया। संगठन के सभी अभियानों की लगातार मॉनीटरिंग कर रहे प्रदेश अध्यक्ष श्री देव जल्द ही पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह

है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने चिकित्सकीय बुलेटिन के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि श्री देव के कमर के ऊपरी हिस्से में किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी थी। कमर के निचले हिस्से में एक छोटा सा फ्रैक्चर था, जिसके उपचार हेतु एक छोटी-सी सफल सर्जरी की गई थी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि चिकित्सकीय बुलेटिन के अनुसार फ्रैक्चर अब तेजी से ठीक हो गया है और रिकवरी की स्थिति बेहद संतोषजनक है। डॉक्टरों ने एक स्वास्थ्य श्री देव को स्वस्थ त्रुति पर पूर्ण प्रसन्नता जताई है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि श्री देव अपनी अद्भुत इच्छाशक्ति और लाखों कार्यकर्ताओं की प्रार्थनाओं के बल पर जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ होकर रायपुर लौट रहे हैं। वे शीघ्र ही रायपुर पहुँचकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व पर पुनः पूर्ण ऊर्जा के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार

Mineral Resources Department, Government of Chhattisgarh
Directorate of Geology & Mining
Indravati Bhavan, Block-4, Second Floor, Nawa Raipur
Atal Nagar, Raipur, Chhattisgarh - 492002, India

31 August 2026

Notice Inviting Tender

Invitation for Bids for grant of 02 Mining Lease (ML) and 01 Composite Licence (CL)
Limestone Ore Block

In exercise of the powers conferred by Sections 10B and 11 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, and in accordance with the Mineral (Auction) Rules, 2015 (as amended from time to time) notified thereafter, the Mineral Resources Department, Government of Chhattisgarh, has identified the following mineral blocks for grant of mining lease/composite licence through electronic auction and hereby invites bids for the purpose of granting mining lease/composite licences:

Sl No	Name of the Block	mineral	District	Type of Mineral concession	Area (Ha)	Level of Exploration	Tender Price (INR)*
1	Dhabadhi North Limestone Block	Limestone	Janjgir-Champa	ML	414.00	G3	5 Lakhs
2	Dhabadhi South Limestone Block	Limestone	Janjgir-Champa	ML	394.00	G3	5 Lakhs
3	Khairwahi Limestone Block	Limestone	Balod	CL	700.00	G4	2 Lakhs

***Excluding GST**

Accordingly, Financial bids are invited in digital format only and technical bids are invited both in digital and physical format from Eligible bidders.

Terms and conditions, deadlines etc. for participating in the electronic auction are provided in the Tender Document. The Model Tender Document for the mineral blocks and mineral block summary are available free of cost in electronic form and can be downloaded from the website of MSTC Ltd.(<https://mstcecommerce.com/auction/home/mcln/index.jsp>) and websites of Mineral Resources Department, Government of Chhattisgarh (<https://chhattisgarhmines.gov.in>) for the purpose of information only.

Those interested and eligible for bidding can participate in the bidding only after online purchase of the Tender Document on payment of the non-refundable tender fee as mentioned above (Applicable Goods and Service Tax(GST) shall be payable on Reverse Charge Mechanism), from the website of e-auction platform provider MSTC Ltd. Bidder shall be able to make payment of the Tender Document fee through RTGS/ net banking (through the payment gateway of e-auction platform). After registration at MSTC website, interested & eligible bidders can purchase the Tender Document. On successful registration, eligible bidders will obtain Login ID and password necessary for participation in the e- auction process.

The last date for online purchase of Tender Document is Wednesday, 14th October and the last date for submission of the bid is 15:00 Hours IST on Thursday, 15th October. Any further communications, amendments etc. shall be available on the above website of MSTC and the websites of Mineral Resources Department, Government of Chhattisgarh.

Director
Geology & Mining, Chhattisgarh

G-262703017/8

भागवत ने अपने संबोधन से विरोधियों को निःशब्द किया

अवधेश कुमार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कार्यक्रम की सफलता से अमरीका से लेकर भारत तक के विरोधियों को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सटीक उत्तर मिल गया है। भारत में नेताओं ने कार्यक्रम से पूर्व अपने बयानों से इसके विरोध में माहौल बनाने की कोशिश की। दूसरी और अमरीका में कुछ संगठन, जैसे हिंदुज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कार्जिसिल, इंटरफेथ सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क आदि ने जितना संभव हुआ कार्यक्रम को ही रोकने की कोशिश की। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि एक ऐसे आंदोलन का उभार देखना बेहद परेशान करने वाला है, जो एक बहिष्कारवादी सोच पर आधारित है। यू.एस. कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अमरीकी सरकार से संघ के सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने और भारत में कथित धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों को लेकर मोहन भागवत का वीजा रद्द करने तक पर विचार करने का आग्रह कर दिया। वाशिंगटन स्थित इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कार्जिसिल ने ऐसी वैन निकाली, जिसमें वीडियो स्क्रीन लगी थी और जो मैनहट्टन की सड़कों पर घूमकर कार्यक्रम के विरुद्ध प्रचार कर रही थी। हालांकि इसका परिणाम हुआ कि अमरीकी मीडिया में इस कार्यक्रम को बिना कोशिश के लगातार कवरेज प्राप्त हो गई। ऐसा नहीं था कि सब कुछ एकपक्षीय था। उदाहरण के लिए अमरीकी गायिका मेरी मिलबेन ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर ममदानी और विरोधियों की आलोचना की। ऐसी प्रतिक्रिया देने वाले और भी कई अमरीकी प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वास्तव में भागवत ने अपने संबोधन में उसी भाव को सामने रखा, जो कार्यक्रम का उद्देश्य बताया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र केवल भौगोलिक इकाइयां नहीं, एक दायित्व का निर्वाह करते हैं। भारत का दायित्व है कि वह विविधता में एकता के इस सत्य का साक्षात्कार करे और समय-समय पर संसार को भी इस सत्य का साक्षात्कार कराए। वननेस क्या है, इसका उत्तर देते हुए भागवत ने कहा कि भौतिक सुख स्थायी सुख या समाधान नहीं हैं। सच है कि केवल भौतिक सुख और उपलब्धियों के कारण ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्रों के बीच समस्याएं बढ़ी हैं। इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन के बोधवाक्य ‘आत्मनोः मोक्षार्थं जगत् हितायच’ की बात की। यानी अपनी आत्मा का मोक्ष विश्व कल्याण में ही निहित है। मैं आप में हूँ, और आप मेरे में हैं, हम सब एक-दूसरे में समाए हैं, यही वननेस है। भारतीय होने के नाते हमें संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ इस विचार को अपने आचरण से फैलाना है। आप सोचिए, इस तरह के संबोधन में किस पहलू का विरोध हो सकता है ? उन्होंने यह भी कहा कि विश्व में दो प्रकार के लोग हैं। एक कहते हैं, ‘जियो और जीने दो’। दूसरे कहते हैं कि ‘मात्र उन्हीं को जीने का अधिकार है, जो हमारी बात मानते हैं’। हम उन्हीं की रक्षा करेंगे, जो हमारे मत को मानेंगे।’ यह दूसरे प्रकार के लोग असुर श्रेणी में आते हैं और पहले प्रकार के लोग देव कहलाते हैं। क्या यह सच नहीं कि अमरीका सहित अनेक देशों ने अपना चरित्र यही दिखाया है और इसी कारण विश्व तनाव, संघर्ष सहित अनेक जटिलताओं और समस्याओं में उलझा हुआ है ? यही नहीं इसी सोच से निर्मित संगठन और व्यक्ति भी हमारे सामने हैं। सच कहें तो संघ, हिंदुत्व, हिंदू और भारत के वास्तविक व्यापक दृष्टिकोण को रखकर भागवत ने विरोधियों को निःशब्द कर दिया। किंतु जिन्हें कुछ मानना ही नहीं है और जिनके अंदर रोग के स्तर पर संघ का विरोध है, वे न पहले माने हैं, न आगे मानेंगे। वे जो कुछ बोलते हैं, प्रचारित करते हैं, लिखते हैं, वह सब झूट पर आधारित होता है।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

कुछ अदूरदर्शी महाशय भारतीय चिकित्सा-शास्त्र पर अपूर्णता का मिथ्या आक्षेप किया करते हैं परन्तु हम उन्हें दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि आयुर्वेद के चरक सुश्रुत आदि सिद्ध ग्रन्थों का तो जिक्र ही क्या है, यदि हम पुराण ग्रन्थों की घरेलू दवाओं को भी बर्ताव में लाने लेंगे तो हमारी दैनिक आवश्यकता पूर्ण करने के लिए तो विश्वविद्या-भण्डार हमारे पुराण ही पर्याप्त हैं। उदाहरणार्थ हम यहां पुराणोक्त चिकित्सा शास्त्र का कुछ दिदर्शन करते हैं।

गजायुर्वेद

बालबिल्वं तथा लोधं धातको सितया सह ।

अतिसारविनाशाय पिण्डी भुञ्जीत कुञ्जरः ॥

(अग्नि पु० अ० 286)

अर्थात्- यदि हाथी से दस्त बन्द करने हों तो छोटे बेल, जोध, और आवलों को कूट कर मिश्री मिला कर पिण्डये बना हाथी को खिला दें, इससे दस्त बन्द



हो जाएंगे। इसीप्रकार हाथियों के अन्यान्य रोगों की चिकित्सा भी पुराणों में लिखी है।

अश्रायुर्वेद

गोमयं लवणं मूत्रं कृथितं मृत्यमन्वितम् ।

अङ्गुलेपो मक्षिकादिदंशश्रमधिनाशकः ॥

(अग्नि पु० अ० 228)

अर्थात्-गोबर, नमक, मिट्टी इनको गोमूत्र में पका कर यदि घोड़े के शरीर पर लगाया जावे तो मच्छर आदि द्वारा डसे हुवे घोड़े का जहर उतर जाता है। (यह नुसखा अनुभूत है आजकल काम में आता है)। हिंगुष्फरमूलज्ज नागरं साम्लवेतसम् ।

पिप्पलोस्सैधवयुतं शूलघ्नं चोष्णवारिणा ॥

(अग्नि पु० अ० 286)

अर्थात्- हिंग, पोखरमूल, नागरमोथा, अम्लवेत, निम्बूखिजोरा, पिप्पली, सेंधा मक्त इनको कूट छानकर घोड़े को गर्भ जल से देने पर पेट दर्द दूर होता है।

क्रमशः ...

डोभाल की कूटनीति और भारत-चीन संबंधों की नई कस्वत

ललित गर्ग

भारत और चीन के संबंधों में पिछले कुछ वर्षों की तल्खी के बाद अब संवाद, संयम और व्यावहारिक सहयोग का एक नया दौर दिखाई दे रहा है। इसे किसी अचानक आए परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा, कूटनीति और राष्ट्रीय हितों को साथ लेकर चलने वाली एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। इस बदलते परिदृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनकर सामने आई है। 25 अगस्त को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता ने इस प्रक्रिया को ठोस आधार दिया है। दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने, सीमा निर्धारण की दिशा में शीघ्र एवं सार्थक प्रगति करने तथा सैन्य-द्विपक्षीय संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने पर सहमति बनाई है। डोभाल की बीजिंग यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह केवल सीमा विवाद पर बातचीत नहीं थी। यह उस व्यापक प्रश्न पर विमर्श था कि क्या भारत और चीन प्रतिस्पर्धा के बावजूद सह-अस्तित्व, स्थिरता और पारस्परिक हितों का रास्ता तलाश सकते हैं। दोनों देशों ने दो अतिरिक्त सैन्य संपर्क-बिंदु और पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में दो अतिरिक्त सैन्य दूरभाष संपर्क व्यवस्था करने पर सहमति जताई है। सीमा व्यापार, कैलाश-मानसरोवर यात्रा और सीमा-पार सहयोग को भी आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ है। अजीत डोभाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सुरक्षा और कूटनीति को परस्पर विरोधी नहीं मानते। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है-मजबूत सुरक्षा-व्यवस्था ही प्रभावी कूटनीति की आधारभूमि बन सकती है। चीन के संदर्भ में भी भारत का संदेश यही रहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के बिना द्विपक्षीय संबंधों का पूर्ण सामान्यीकरण संभव नहीं है। 25वें दौर की वार्ता में यही भारतीय दृष्टिकोण प्रमुखता से सामने आया। डोभाल का व्यक्तित्व केवल वार्ताकार का नहीं, बल्कि सुरक्षा रणनीतिकार का है। वे लंबे समय तक खुफिया तंत्र में रहे, विभिन्न



संवेदनशील क्षेत्रों में काम किया और बाद में खुफिया ब्यूरो के प्रमुख बने। भारत सरकार के अनुसार, उन्होंने पूर्वोत्तर, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान से जुड़े सुरक्षा मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उनकी कार्यशैली में एक उल्लेखनीय संतुलन दिखाई देता है- जहां आवश्यक हो वहां कठोरता और जहां अवसर हो वहां संवाद। उड़ी के बाद की सर्जिकल कार्रवाई, बालाकोट की कार्रवाई, डोकलाम संकट के दौरान कूटनीतिक प्रयास और आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में उनकी भूमिका इसी व्यापक दृष्टिकोण के उदाहरण माने जाते हैं। 2026 में उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में उनके योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया।

भारत-चीन संबंधों का सबसे कठिन दौर वर्ष 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद आया। चार वर्षों तक सीमा पर सैन्य तनाव बना रहा। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच सैनिकों की पूर्ण वापसी और संबंधित विवादों के समाधान के बाद संबंधों को धीरे-धीरे पटरी पर लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसी वर्ष कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति तथा मतभेदों को संबंधों की समग्र दिशा को प्रभावित न करने देने पर जोर दिया था। यही वह बिंदु था जहां डोभाल की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। दिसंबर 2024 में विशेष

ज्ञान/मीमांसा

हर मुद्दे में जाति का कोण क्यों ढूँढ़ने लगी है कांग्रेस?

नीरज कुमार दुबे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं, जिनके जरिए वह दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और युवाओं के बीच एक नया सामाजिक गठजोड़ तैयार करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या देश को आगे ले जाने की राजनीति अतीत के विवादों को लगातार कुरेदकर होगी, या भविष्य के भारत की चुनौतियों का समाधान खोजकर ?

राहुल गांधी के हालिया बयानों और राजनीतिक गतिविधियों से यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस अब एक नए सामाजिक समीकरण पर काम कर रही है। उनकी राजनीति का निशाना दलित, ओबीसी, महिलाएं, जेन-जी और अल्पसंख्यक हैं। पुणे के कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों पर बात करते हुए राहुल गांधी ने पितृसत्ता को चुनौती देने की बात की और आरएसएस तथा भाजपा पर ऋमनुस्मृति की मानसिकता**ख** खरने का आरोप लगाया।

देखा जाये तो महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता जैसे मुद्दे निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं। इन पर जितनी गंभीर चर्चा हो, उतना बेहतर है। लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं के आधुनिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए क्या हर बार हजारों वर्ष पुराने ग्रंथों को राजनीतिक कठघरे में खड़ा करना आवश्यक है ? राहुल गांधी ने पुणे में महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक कठिनाइयों और स्वतंत्र निर्णय लेने की समस्याओं को सुना। यह लौकतांत्रिक राजनीति का स्वाभाविक और स्वागतयोग्य हिस्सा है। लेकिन इसी विमर्श में मनुस्मृति को प्रमुख राजनीतिक हथियार बनाना एक अलग राजनीतिक संदेश देता है।

साथ ही ऐसा लगता है कि राहुल गांधी मनुस्मृति का मुद्दा उठाकर दलित समाज तक भी पहुंच बनाना चाहते हैं। इसका ऐतिहासिक कारण भी है। 1927 में डॉ. बीआर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था और जातिगत भेदभाव तथा असमानता के विरुद्ध संघर्ष को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया था। राहुल गांधी संभवतः इसी ऐतिहासिक स्मृति और वर्तमान के कथित असंतोष को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी महिला अधिकारों का मुद्दा, दलित अस्मिता का प्रश्न और जातिगत न्याय की राजनीति, तीनों को एक साझा राजनीतिक नैरेटिव में पिरोने का प्रयास हो रहा है। लेकिन यहां राहुल



गांधी की राजनीति पर गंभीर सवाल उठता है। क्या हर सामाजिक समस्या का समाधान जाति के चरमे से ही खोजा जाएगा ?

भारत आज 21वीं सदी की तीसरे दशक में है। देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आधुनिक शिक्षा, रोजगार, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में राजनीति का मुख्य प्रश्न यह होना चाहिए कि भारत अगले 25 वर्षों में दुनिया की अग्रणी शक्ति कैसे बनेगा ? लेकिन राहुल गांधी की राजनीति बार-बार समाज को उसके पुराने जातीय खांचों में वापस ले जाती दिखाई देती है।

ऐसे में कानूनविद और भारत के विधि आयोग के पूर्व सदस्य तहिर महमूद की टिप्पणी महत्वपूर्ण हो जाती है। महमूद का कहना है कि मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों को उनके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। केवल औपनिवेशिक काल में किए गए अंग्रेजी अनुवादों के आधार पर उनकी अंतिम व्याख्या कर देना उचित नहीं है। हम आपको बता दें कि महिलाओं के संबंध में मनुस्मृति के उस प्रसिद्ध श्लोक को अक्सर उद्धृत किया जाता है, जिसमें बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र द्वारा महिला की रक्षा की बात कही गई है। आधुनिक दृष्टि से यह व्यवस्था निश्चित रूप से महिलाओं की पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार से मेल नहीं खाती। लेकिन तहिर महमूद का तर्क है कि इसमें प्रयुक्त संस्कृत शब्दों और उनके अनुवाद को लेकर गंभीर मतभेद हैं। उनके अनुसार, रक्षा का अर्थ केवल नियंत्रण नहीं, बल्कि सुरक्षा और संरक्षण भी हो सकता है। दरअसल, औपनिवेशिक दौर के कुछ शाब्दिक अनुवादों ने यह धारणा मजबूत की कि मनुस्मृति

बात है, लेकिन एक तथ्य महत्वपूर्ण है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की व्याख्या कोई टीवी डिबेट की तत्कालिक राजनीतिक बहस नहीं है। यह भाषा, इतिहास, समाज और विधि की गंभीर विशेषज्ञता का विषय है। किसी एक श्लोक को संदर्भ से काटकर पूरे ग्रंथ का अंतिम फैसला सुना देना बौद्धिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। हम आपको बता दें कि तहिर महमूद ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। उनके अनुसार, मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों को सामान्य रूप से हिंदू कानून कहना भी काफी हद तक ब्रिटिश शासनकाल की वर्गीकरण पद्धति का परिणाम है। जिस दौर में ये ग्रंथ लिखे गए, उस समय आज जैसी आधुनिक धार्मिक पहचान और कानूनी व्यवस्था मौजूद नहीं थी। महमूद का तर्क है कि जिस प्रकार रोमन कानून को केवल ईसाई कानून नहीं कहा जाता, उसी तरह प्राचीन भारतीय कानूनी और सामाजिक ग्रंथों को भी केवल आधुनिक धार्मिक पहचान के संकीर्ण दायरे में नहीं बांधा जाना चाहिए।

यह दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने भारत को समझने के लिए कई कठोर श्रेणियां बनाई थीं। अंग्रेजों ने हिंदू, मुस्लिम, जाति, कानून और समुदाय की ऐसी परिभाषाएं बनाई, जिन्हें बाद में भारतीय राजनीति ने भी अपना लिया। विडंबना यह है कि आज भी कई राजनीतिक बहसें उन्हीं औपनिवेशिक व्याख्याओं के आधार पर चल रही हैं।

यहां कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि भारत, भारतीय संविधान से चलता है। संविधान सर्वोपरि है। समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकार आधुनिक भारत की मूल संवैधानिक प्रतिबद्धताएं हैं। लेकिन इसका अर्थ

रावण को हराने वाले शक्तिशाली कार्तवीर्य अर्जुन आखिर परशुराम से कैसे हारे

आशुतोष गर्ग

पुराणों में कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता है, सबसे शक्तिशाली राजाओं में गिने जाते हैं। कहा जाता है कि युद्ध के समय उनके शरीर में एक हजार भुजाएं प्रकट हों। दूसरा, यदि कभी वह अधर्म के मार्ग पर जाएं तो साधु-संत उन्हें सही रास्ता दिखाएं। तीसरा, पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर धर्मपूर्वक शासन करने की शक्ति मिले। चौथा, उनकी मृत्यु केवल उनसे अधिक शक्तिशाली वीर के हाथों हो।

वादान मिलने के बाद कार्तवीर्य अर्जुन ने सातों द्वीपों, समुद्रों और अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में पहचान बनाई। उनके शासन में प्रजा सुखी बताई गई है। उन्होंने सात सौ भव्य यज्ञ किए, जिनमें देवता और गंधर्व भी उपस्थित होते थे। देवर्षि नारद ने उनके यज्ञ, दान, तप, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान की प्रशंसा

से प्रसन्न होकर दत्तात्रेय ने उन्हें चार वरदान दिए। पहला, युद्ध के समय एक हजार भुजाएं प्रकट हों। दूसरा, यदि कभी वह अधर्म के मार्ग पर जाएं तो साधु-संत उन्हें सही रास्ता दिखाएं। तीसरा, पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर धर्मपूर्वक शासन करने की शक्ति मिले। चौथा, उनकी मृत्यु केवल उनसे अधिक शक्तिशाली वीर के हाथों हो।

वादान मिलने के बाद कार्तवीर्य अर्जुन ने सातों द्वीपों, समुद्रों और अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में पहचान बनाई। उनके शासन में प्रजा सुखी बताई गई है। उन्होंने सात सौ भव्य यज्ञ किए, जिनमें देवता और गंधर्व भी उपस्थित होते थे। देवर्षि नारद ने उनके यज्ञ, दान, तप, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान की प्रशंसा



कार्तवीर्य अर्जुन का पराक्रम केवल

धरती तक सीमित नहीं था। उन्होंने

कर्कोटक नाग के पुत्रों को पराजित कर

माहिष्मती में बसाया। नर्मदा नदी की धारा

को अपनी सहस्र भुजाओं से रोक दिया।

समुद्र में उतरकर इतनी तेज लहरें उठाईं कि

बड़े-बड़े जलचर और पाताल के दैत्य भी

भयभीत हो गए। एक बार उन्होंने लंकापति

रावण को युद्ध में हराकर धनुष की प्रत्यंघ

से बांध लिया था। बाद में महर्षि पुलस्त्य

के अनुरोध पर उन्हें मनुष्य किया। एक अन्य

प्रसंग में अग्निदेव को अपना राज्य दान देने

की थी। कहा जाता है कि योगबल के कारण वह एक साथ कई स्थानों पर पहुंचकर प्रजा की रक्षा करते थे। वह खेतों और यज्ञों की सुरक्षा करते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर वर्षा भी कराते थे।

कार्तवीर्य अर्जुन का पराक्रम केवल

धरती तक सीमित नहीं था। उन्होंने

कर्कोटक नाग के पुत्रों को पराजित कर

माहिष्मती में बसाया। नर्मदा नदी की धारा

को अपनी सहस्र भुजाओं से रोक दिया।

समुद्र में उतरकर इतनी तेज लहरें उठाईं कि

बड़े-बड़े जलचर और पाताल के दैत्य भी

भयभीत हो गए। एक बार उन्होंने लंकापति

रावण को युद्ध में हराकर धनुष की प्रत्यंघ

से बांध लिया था। बाद में महर्षि पुलस्त्य

के अनुरोध पर उन्हें मनुष्य किया। एक अन्य

प्रसंग में अग्निदेव को अपना राज्य दान देने

के बाद वन जलने लगे और उसी आग में महर्षि वसिष्ठ का आश्रम भी नष्ट हो गया। इससे क्रोधित होकर महर्षि वसिष्ठ ने शाप दिया कि उनका अंत भृगुवंशी परशुराम के हाथों होगा।

कहा जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन के

सैनिक अहंकार में महर्षि जमदग्नि के

आश्रम पहुंचे और उनकी हत्या कर दी। इस

घटना के बाद भगवान परशुराम ने कार्तवीर्य

अर्जुन को युद्ध की चुनौती दी। भीषण युद्ध

में परशुराम ने अपनी दिव्य शक्ति से

कार्तवीर्य अर्जुन की एक-एक करके सभी

सहस्र भुजाएं काट डालीं और अंत में उनका

वध कर दिया। इस तरह भगवान दत्तात्रेय

का दिया हुआ वरदान भी पूरा हुआ, क्योंकि

उनकी मृत्यु उनसे अधिक शक्तिशाली योद्धा

के हाथों हुई। कार्तवीर्य अर्जुन के एक हजार

पुत्र बताए जाते हैं। इनमें जयध्वज, सूरसेन,

वृषभ, मधु और ऊर्जित प्रमुख थे।

आज का इतिहास

- 1573 अकबर ने गुजरात फ़तह किया ।
- 1666 लंदन में भीषण आग लगने से छह लोगों की मौत हुई और दस हजार इमारतें नष्ट हो गयीं ।
- 1775 पहले अमेरिकी युद्ध पोत ‘हाना’ का जनरल जॉर्ज वाशिंगटन ने जलावतरण किया गया ।
- 1789 अमेरिका में राजस्व विभाग बनाया गया ।
- 1926 इटली और यमन में हुए समझौते के तहत लाल सागर तट पर इटली का वर्चस्व कायम हुआ ।
- 1930 ‘क्रेश्चन मार्क’ नामक विमान ने यूरोप से अमेरिका के लिए बिना कहीं रुके पहली बार उड़ान भरी ।
- 1945 जापान द्वारा हार स्वीकार कर लिए जाने के बाद छह साल तक चला दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ ।
- 1945 हो ची मिन्ही ने स्वतंत्र वियतनाम गणराज्य की स्थापना की ।
- 1946 जवाहर लाल नेहरू के उप सभापतिपदों में अंतरिम भारत सरकार का गठन ।
- 1956 हैदराबाद से सी किलोमीटर दूर जडचेराला और महबूब नगर के बीच पुल द्दहने से 125 लोगों की मौत ।
- 1962 सोवियत संघ क्यूबा को हथियार देने पर राजी हुआ ।
- 1969 अमेरिका के न्यूयॉर्क में पैसे निकालने वाली मशीन ऑटोमैटिक टैलर मशीन (ए.टी.एम.) को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया ।
- 1970 कन्याकुमारी में विवेकानन्द स्मारक का उद्घाटन हुआ ।
- 1990 काला सागर में सोवियत यात्री जहाज के डूबने से 79 यात्री मारे गए ।
- 1998 डरबन में 12वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा उद्घाटन ।
- 1996 मुस्लिम विद्रोहियों और फिलीपींस सरकार ने 26 वर्षों से जारी विद्रोह को समाप्त करने के एक समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। इस दौरान एक लाख 20 हजार से अधिक लोग मारे गये थे।
- 1992 अमेरिका और रूस अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए संयुक्त उपक्रम बनाने पर सहमत हुए।
- 1999 भारतीय तैराक बुला चौधरी इंग्लिश चैनल दो बार पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बनीं।
- 2000 मैनहट्टन परियोजना में अग्रणी भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक जॉन सिम्प्सन का निधन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र प्रणाली की तैनाती की योजना स्थगित।
- 2009 अफ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. रेड्डी को ले जा रहा हेलीकाप्टर उड़ान भरने के बाद लापता हुआ।

‘मांझी’ और ‘चिराग’ के बीच क्या मोड़ लेगा ‘क्रीमी लेयर’ का संघर्ष ?

अजय बोकिल

देश में जातिवार जनगणना कैसी हो रही है, इसके अंतिम आंकड़े केन्द्र सरकार जारी करेगी या नहीं या फिर इसके राजनीतिक लाभ-हानि के मद्देनजर ‘उचित समय’ पर करेगी, ये तमाम बातें अभी अटकलों के दायरे में ही हैं, लेकिन जातिवाद का गढ़ समझे जाने वाले बिहार में दलितों में सरकारी नौकरियों के लिए ‘क्रीमी लेयर’ की शर्त लागू करने अथवा न करने को लेकर नया राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया है।

इसे नियम को लागू करने की मांग और विरोध करने वाले दोनों ही दल सत्तारूढ़ एनडीए के घटक हैं और दोनों के ही नेता दलित हैं। हिंदुस्तानी अवाग पार्टी (सेक्युलर) के नेता और केन्द्रीय मंत्री जीवनराम मांझी ने अनुसूचित जाति श्रेणी में आरक्षण के लिए ओबीसी की तर्ज पर क्रीमी लेयर की शर्त जोड़ने की मांग की है ताकि आरक्षण का लाभ उन दलित जातियों तक भी पहुंचे, जो अब तक इससे वंचित रही हैं। इसके विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चुनौती के अंदाज में कहा कि अगर मांझी दलित आरक्षण में क्रीमी लेयर लाना चाहते हैं तो पहले पद से इस्तीफा दें।

उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री और जीवनराम के बेटे संतोष सुमन पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आरक्षण का आधार

सामाजिक भेदभाव और छुआछूत है, न कि आर्थिक। अगर क्रीमी लेयर जैसे मुद्दे पर बात करनी है तो चर्चा संसद में हो। उधर संतोष सुमन का तर्क है कि उनकी मांग आरक्षण समाप्त करने की नहीं, बल्कि कोटे में कोटा लागू करने और आरक्षण का लाभ सर्वाधिक वंचित समुदायों तक पहुंचाने की है।

इसके पहले संतोष सुमन ने सवाल उठाया था कि अगर पिछड़े वर्ग में ‘अति पिछड़ा’ और सामान्य वर्ग में ‘इंडब्लूएस’ की अलग व्यवस्था है तो एससी वर्ग के भीतर सबसे वंचित समूहों की पहचान क्यों नहीं की जा सकती? क्रीमी लेयर पर मचे इस घमासान पर एनडीए की सबसे बड़ी घटक पार्टी भाजपा खामोश है। अलबत्ता इस विवाद में कूदते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार, उषेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीवन राम मांझी की पार्टियों की आरक्षण को लेकर स्पष्ट विचारधारा क्या है, यह कोई नहीं जानता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण खत्म करने के विचार की पब्लिक रैलिंग कर रही है। लंबे अरसे बाद में देश में आरक्षण खत्म करने या उसकी समीक्षा करने तथा आरक्षित श्रेणियों में भी क्रीमी लेयर नियम लागू करने का मुद्दा नए सिरे से गरमा रहा है। इसमें पंच यह है कि क्रीमी लेयर पर आरक्षित जातियों में ही इस बात पर तलवारें खिंची हैं कि आरक्षण



का लाभ किस जाति को कितना मिला और कौन कितना वंचित रहा। उधर ‘हिंदू एकता’ की बात करने वाली भाजपा के सामने यह सिर्फ आरक्षण के औचित्य पर बहस भर नहीं बल्कि जटिल राजनीतिक चुनौती है। इस मामले में वह असमंजस की स्थिति में है।

सवाल है कि जीवनराम मांझी ने आरक्षित अनुसूचित जाति वर्ग में भी ‘क्रीमी लेयर’ का मुद्दा क्यों उछाला? इसके पीछे राजनीतिक मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ आरक्षित जातियों में समाजार्थिक समता तक सीमित है अथवा यह आरक्षित वर्ग में ही वर्चस्व की लड़ाई है? इस लड़ाई के दूरगामी परिणाम क्या होंगे? क्या इसकी गूंज अन्य राज्यों में भी होगी? आरक्षण में निहित मूल भाव सामाजिक समता और अवसरों की समानता का क्या होगा? कहीं यह संघर्ष राजनीतिक छीना झपटी

में तो नहीं बदल जाएगा? इसके पहले बिहार में आरक्षित अनुसूचित जातियों के गणित को समझना होगा। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जमाने में दलितों को समाजार्थिक उत्थान के हसाब से दो श्रेणियों दलित और महादलित में बांटा गया था। इसमें पासवान जाति को 21 जातियों को ‘महादलित’ घोषित किया गया था, जिसमें जीवनराम मांझी की मुसहर जाति भी है। 2014 में नीतीश ने पार्टी में भीतरी बगawat रोकने के लिए सीएम पद से इस्तीफा देकर महादलित जीवनराम मांझी को सीएम बना दिया था और नौ माह बाद हटा भी दिया था।

इससे नाराज जीवनराम ने जद (यू) छोड़ अपनी नई हिंदुस्तानी अवाग पार्टी बना ली। बिहार में दलितों की जनसंख्या करीब 16 फीसदी है। राज्य में महादलित मुसहर जाति की कुल संख्या करीब 40 लाख बताई जाती है, जो कि बिहार की आबादी का लगभग 3.08 फीसदी है। यह राज्य की तीसरा सबसे बड़ा एससी समूह है। जबकि पासवान जाति की संख्या करीब 70 लाख बताई जाति है, जो राज्य की कुल आबादी का 5.31 फीसदी हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अनुसूचित जाति वर्ग में नौकरियों में आरक्षण का सर्वाधिक लाभ पासवान, रविदासी और थोबी जाति ने उठाया है।

इसका एक कारण इन जातियों का तुलनात्मक रूप से ज्यादा संगठित और राजनीतिक रूप से मुखर होना भी है। जीवनराम का मानना है कि क्रीमी लेयर नियम लागू होने पर बाकी की अनुसूचित जातियों की नौकरियों और शिक्षा में हिस्सेदारी बढ़ सकेगी। जहां तक आरक्षित श्रेणियों में क्रीमी लेयर लागू करने की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में राज्यों को एससी/ एसटी श्रेणियों के भीतर उप वर्गीकरण (सबकोटा लागू करने) की अनुमति दी थी तथा आर्थिक रूप से सम्पन्न दलितों को आरक्षण के दायरे से बाहर करने का सुझाव दिया था। तब सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवंई थे, जो स्वयं दलित समुदाय से थे। उनका यह फैसला व्यापक संदर्भ में था। हालांकि मोदी सरकार ने इस फैसले के राजनीतिक खतरों को भांपकर सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में एससी/एएसटी आरक्षण में आय आधारित ‘क्रीमी लेयर’ नियम लागू करने का विरोध किया। गौरतलब है कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में पिछड़े वर्ग के लिए ‘क्रीमी लेयर’ नियम लागू है, जिसके तहत विभिन्न स्रोतों से 8

लाख रू. तक की वार्षिक आय वाले परिवार को क्रीमी लेयर माना जाता है।

हालांकि भाजपा शासित हरियाणा देश का ऐसा पहला ऐसा राज्य है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अपने यहाँ रूप ‘ए’ और ‘बी’ की सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा लागू करने को मंजूरी दी। लेकिन कानूनी और व्यावहारिक पेचीदगियों के कारण सरकार ने इसके अमल पर रोक लगा दी। अब सवाल यह है कि जब मांझी और चिराग दोनों ही बिहार में महादलित जातियों से आते हैं तो फिर यह लड़ाई क्यों?

चिराग एससी में क्रीमी लेयर का विरोध इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर सच में ऐसा हुआ तो उनकी जाति की नौकरियों और शिक्षा में हिस्सेदारी कम हो सकती है। जबकि मांझी का मानना है कि अत्यंत पिछड़ी और वंचित दलितों के उत्थान की खातिर उन दलितों को त्याग की उदारता दिखानी चाहिए, जो पहले ही आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, जिनका आर्थिक उन्नयन हो चुका है और जो दूसरी-तीसरी पीढ़ी तक इसका फायदा उठाते आ रहे हैं। यानी कहीं तो आरक्षण की मर्यादा तय हो। या यूं कहें कि जो जो जाति आरक्षण का लाभ लेकर उन्नत होती जाए, वह अपने इस लाभ को सीमित करे।

भारत-चीन सीमा विवाद की कठिन डगर

आनंद कुमार

भारत और चीन के संबंध एक बार फिर ऐसे मोड़ पर हैं, जहां वर्षों की सैन्य तनातनी, कूटनीतिक अविश्वास और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएससी) पर लंबे गतिरोध के बाद दोनों देश संबंधों को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की हालिया वार्ता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि बातचीत अब केवल सीमा पर तनाव को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं दिवती, बल्कि दोनों पक्षों ने सीमा निर्धारण में ‘शीघ्र और ठोस प्रगति’ की बात भी की है। यह सकारात्मक संकेत है, पर असली परीक्षा यह होगी कि इस अभिव्यक्ति को ठोस वार्ता प्रक्रिया और वास्तविक प्रगति में कितना बदला जा सकता है। पिछले दो दशकों से भारत और चीन ने अपने मतभेदों को अलग-अलग रखने की कोशिश की। सीमा विवाद के बावजूद, आर्थिक संबंध तेजी से बढ़े, व्यापार बढ़ा और दोनों देश ब्रिक्स समेत अनेक बहुपक्षीय मंचों पर साथ काम करते रहे। लेकिन, परस्पर आर्थिक निर्भरता सीमा विवाद से पैदा हुए रणनीतिक अविश्वास को दूर नहीं कर सकी। वर्ष 2020 के गलवां संघर्ष और पूर्वी लड़ाख में लंबे सैन्य गतिरोध ने पुराने समीकरण बदल दिए। इससे स्पष्ट हुआ कि सीमा पर शांति को केवल मौजूदा व्यवस्थाओं के सहारे अनिश्चितकाल तक कायम नहीं रखा जा सकता। इसके बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के माध्यम से तनाव कम करने का प्रयास किया। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत-चीन संबंध पुराने दौर में लौट आए हैं। दोनों देश अब एक ऐसे संबंध की तलाश कर रहे हैं, जिसमें रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ स्थिरता और संवाद के लिए भी जगह हो। विशेष प्रतिनिधियों की हालिया वार्ता का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इसमें सीमा प्रबंधन से आगे बढ़कर सीमा निर्धारण पर ध्यान देने की

इच्छा दिखाई दी है। सैन्य कमांडरों की बैठक, राजनयिक संपर्क और अन्य संवाद तंत्र ने स्थानीय घटनाओं को बड़े संघर्ष में बदलने से रोकने में भूमिका निभाई है। एलएससी के कई हिस्सों में सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित न होने के कारण गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने आ जाते हैं। बेहतर संचार गलतफहमी और आकस्मिक तनाव को रोक सकता है। लेकिन, संकट प्रबंधन सीमा विवाद का स्थायी विकल्प नहीं हो सकता। इसी कारण ‘अली हार्वेस्ट’, यानी कुछ क्षेत्रों में शीघ्र सीमा निर्धारण की अवधारणा महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में 2005 के ‘राजनीतिक मानदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों’ संबंधी समझौते की पुनर्पुष्टि महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष प्रतिनिधियों को सीमा विवाद के समाधान के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद सीमा का निर्धारण व सीमांकन होना था। इसका पुनः उल्लेख बताता है कि दोनों पक्ष मौजूदा कूटनीतिक ढांचे को बनाए रखना चाहते हैं। अब असली चुनौती इन सिद्धांतों को ऐसे संवाद में बदलने की है, जिससे ठोस नतीजे हासिल हो सकें। भारत व चीन, दोनों समझते हैं कि एलएससी पर लगातार तनाव उनके हित में नहीं है। चीन को अपनी व्यापक आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के लिए स्थिर वातावरण चाहिए, जबकि भारत भी चीन के साथ सीमा तनाव को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं पर अनिश्चितकाल तक हावी नहीं रहने देना चाहेगा। ब्रिक्स और वैश्विक दक्षिण से जुड़े मंचों पर दोनों देशों के बीच संवाद जारी है। फिर भी, इसे रणनीतिक मेल-मिलाप नहीं माना जाना चाहिए। चीन निकट भविष्य में पूरे विवाद के समाधान के बजाय क्रमिक प्रगति को प्राथमिकता दे सकता है। भारत को इस अवसर का उपयोग करना चाहिए, पर यह भी सुनिश्चित करना होगा कि क्रमिकता सीमा विवाद को अनिश्चितकाल तक टालने का माध्यम न बन जाए। सीमा पार नदियों पर सहयोग भी विश्वास निर्माण में उपयोगी हो सकता है।

बिहार के ‘सहयोग मॉडल’ से बाकि राज्यों को भी सीखने की जरूरत

संजीव कुमार मिश्र

क्या किसी सरकारी स्कूल या हॉस्टल में गंदा पानी, खराब खाना या बिजली की किल्लत जैसी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान 30 दिन के भीतर पाना संभव है?...जहां देश के अधिकांश राज्यों में छात्र ऐसी बुनियादी सुविधाओं के लिए महीनों प्रशासनिक चक्कर काटने या सड़कों पर उतरने को मजबूर होते हैं, वहीं बिहार सरकार ने एक पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था से इस धारणा को बदलने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शुरू की गई इस नई पहल ने छात्र शिकायतों के निपटारे का एक ऐसा मॉडल पैर कर दिया है, जिसकी गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है।

छात्रों की शिकायतें अक्सर लंबे समय तक अनुसुलझी रहती हैं, इसकी बड़ी वजह प्रशासनिक प्रक्रिया की जटिलता है। किसी छात्र को हॉस्टल की सफाई, भोजन की गुणवत्ता, बिजली-पानी या फीस से जुड़ी दिक्कत होने पर पहले वार्डन, फिर प्रिंसिपल और जरूरत पड़ने पर जिला शिक्षा कार्यालय तक जाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में न तो कोई तय समयसीमा होती है और न ही स्पष्ट जवाबदेही तय होती है, जिस वजह से छोटी शिकायतें भी हफ्तों-महीनों तक लंबित रह जाती हैं।

बिहार सरकार के विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की खासियत यह है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए दो अलग कैटेगरी बनाई गई हैं — पहली, शैक्षणिक संस्थान यानी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए, और दूसरी, छात्रावास यानी हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए। पोर्टल के होमपेज पर ही यह दोनों विकल्प दिए गए हैं, जिससे छात्र सही कैटेगरी चुनकर सीधे संबंधित फॉर्म तक पहुंच जाते हैं। कैटेगरी चुनने के बाद छात्र के सामने एक सीधा-सादा फॉर्म खुलता है, जिसमें नाम, लिंग, पिता का नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होती है। ईमेल आईडी को वैकल्पिक रखा गया है, ताकि जिन छात्रों के पास ईमेल नहीं है वे भी शिकायत दर्ज करा सकें, जबकि मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरिफाई किया जाता है ताकि हर शिकायत असली छात्र की ओर से ही दर्ज हो।



पोर्टल पर छात्रों के लिए तीन सुविधाएं दी गई हैं। शिकायत दर्ज कराने का विकल्प हॉस्टल सुविधाओं, भोजन, स्वच्छता, सुरक्षा और बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए है। इसके अलावा छात्र व्यवस्था सुधारने से जुड़े अपने सुझाव भी साझा कर सकते हैं, और सबसे अहम बात यह कि एक बार शिकायत दर्ज करने के बाद छात्र उसकी मौजूदा स्थिति और उस पर हुई कार्रवाई को ट्रैक भी कर सकता है। पोर्टल पर सबसे ज्यादा दर्ज होने वाली शिकायतों को भोजन, पेयजल, बिजली, शौचालय-सफाई, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और इंटरनेट जैसी कैटेगरी में पहले से बांटा गया है, जिससे शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचती है और निपटारे में देरी नहीं होती।

पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत का 30 दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। समाधान के बाद संबंधित छात्र को लिखित रूप से इसकी सूचना भी दी जाती है, ताकि यह साफ रहे कि उसकी शिकायत पर वाकई कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता छात्र-छात्राओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, जिससे छात्र बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें। जिन छात्रों के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा नहीं है, उनके लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 भी उपलब्ध कराया गया है। पोर्टल का मकसद छात्रों को शैक्षणिक, परीक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्ति और अन्य संस्थागत समस्याओं का पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से समाधान करना है।

सरकारी पोर्टल और हेल्पलाइन की घोषणाएं आमतौर पर होती रहती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर व्यवहार में

उतनी असरदार साबित नहीं होतीं। लेकिन बिहार सरकार की अब तक की कोशिशों को देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार गंभीरता से छात्रों की समस्याओं को सुनने की ओर अग्रसर है। इस पोर्टल की खासियत है कि इसमें एक जवाबदेही तंत्र भी जोड़ा गया है — तय समयसीमा में शिकायत का समाधान न होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे यह सिर्फ कागजी व्यवस्था बनकर नहीं रह जाती।

पोर्टल के साथ-साथ सरकार ने हर महीने सहयोग शिविर आयोजित करने की व्यवस्था भी बनाई है, जिनमें मंत्री, विधायक, सांसद और संबंधित अधिकारी सीधे स्कूल-कॉलेजों में जाकर छात्रों से बातचीत करेंगे। इन शिविरों में मिलने वाली शिकायतों और सुझावों को भी उसी पोर्टल पर दर्ज कर ट्रैक किया जाता है, जिससे पूरा सिस्टम एक जगह जुड़ा रहता है। यह व्यवस्था खासकर उन इलाकों में उपयोगी मानी जा रही है, जहां छात्र ऑनलाइन माध्यम के बजाय सीधी बातचीत में ज्यादा सहज महसूस करते हैं।

जिन राज्यों में छात्र आंदोलन और कैंपस में असंतोष की घटनाएं सामने आती रही हैं, उनके लिए बिहार का यह मॉडल कुछ स्पष्ट संकेत देता है। शिकायत निवारण तंत्र तभी प्रभावी होता है जब उसमें तय समयसीमा और जवाबदेही दोनों शामिल हों। शिकायत और छात्रावास की समस्याओं को अलग-अलग कैटेगरी में बांटने और फॉर्म को आसान रखने से समाधान की रफ्तार तेज होती है, जबकि स्टैटस ट्रैक करने की सुविधा से छात्रों को भरोसा रहता है कि उनकी बात पर वाकई काम हो रहा है। साथ ही, सिर्फ डिजिटल पोर्टल पर निर्भर रहने के बजाय हेल्पलाइन और जमीनी शिविर जैसे विकल्प भी जरूरी हैं, ताकि हर वर्ग का छात्र इस व्यवस्था से जुड़ सके।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ी घोषणाओं के साथ-साथ जमीनी क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी है। बिहार का अनुभव यह दिखाता है कि अगर शिकायत निवारण तंत्र में पारदर्शिता, आसान प्रोसेस और जवाबदेही तय की जाए, तो नतीजे भी सामने आते हैं। अब देखा जा रहा है कि अपने यहां इसे किस रूप में लागू करते हैं।

मोदी-पुतिन ने दुनिया को दिया बड़ा संदेश

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एससीओ शिखर सम्मेलन में होने वाली मुलाकात से ठीक पहले भारत-रूस रक्षा साझेदारी से जुड़ी दो बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ रूस ने भारत को पांच और एस-400 ट्रायम्फ स्क़ाइन देने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव सौंप दिया है, तो दूसरी तरफ अमेठी के कोरवा में भारतीय सेना के नए ‘शेर’ यानी एके-203 की पूरी तरह स्वदेशी यात्रा निर्णायक पड़ाव पर पहुंच गई है। इस तरह एक ओर मिसाइल कवच भारत के आसमान को अभेद्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ राइफल सीमा पर खड़े सैनिक के हाथ को और मजबूत बना रही है।

हम आपको बता दें कि रूस का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को मिल चुका है और उस पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मार्च 2026 में पांच अतिरिक्त एस-400 स्क़ाइन खरीदने को मंजूरी दी थी। इनकी तैनाती पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों पर किए जाने की संभावना है, जिससे भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। मौजूदा एस-400 बंडे के लिए 280 से अधिक अतिरिक्त मिसाइलें भी खरीदी जा रही हैं, ताकि इंटरसेप्टर का पर्याप्त भंडार बना रहे।

हम आपको बता दें कि एस-400 केवल एक मिसाइल प्रणाली नहीं, बल्कि भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा का बेहद महत्वपूर्ण लंबी दूरी वाला हिस्सा है। यह लड़ाकू विमानों, रणनीतिक विमानों, क़रूज मिसाइलों और अन्य हवाई लक्ष्यों को पहचानने, ट्रैक करने और निशाना बनाने में सक्षम है। उलूआ-अलगा इंटरसेप्टर मिसाइलों के कारण यह विभिन्न उलंचाइयों और दूरियों पर खतरे से निपट सकता है। इसकी कुछ मिसाइलें लगभग 400 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती हैं। कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक और एंगेज करने की क्षमता इसे एयरबेस, कमांड सेंटर और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खास बनाती है।

हम आपको याद दिला दें कि भारत ने 2018 में



पांच एस-400 स्क़ाइन का मूल समझौता किया था। इनमें चार की डिलीवरी हो चुकी है, जबकि पांचवें और अंतिम स्क़ाइन के नवंबर 2026 तक आने की उम्मीद है। नए पांच स्क़ाइन की डिलीवरी समझौते पर हस्ताक्षर के करीब तीन साल बाद शुरू होने की संभावना है। इस तरह भारत अब सिर्फ तात्कालिक जरूरत ही पूरी नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए देश की एयर-डिफेंस छतरी का दायरा भी बढ़ा रहा है।

लेकिन आसमान की सुरक्षा के साथ जमीन पर सैनिक के हाथ में मौजूद हथियार भी उतना ही निर्णायक है। यहीं अमेठी का एके-203 ‘शेर’ कहानी का दूसरा और ज्यादा आत्मनिर्भर चेहरा सामने लाता है। कोरवा स्थित इंडो-रशियन राइफलस प्राइवेट लिमिटेड में बन रही एके-203 पूरी तरह भारतीय कलपुर्जों और सामग्री से बनी है। हालांकि यह रूसी डिजाइन को भारतीय क्षमता में बदलने की करीब एक दशक लंबी यात्रा है। इस परियोजना के लिए रूस से लगभग 90 हजार पत्रों का तकनीकी दस्तावेज मिला था। कोविड महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण तकनीक का हस्तांतरण प्रभावित हुआ और अंतिम टेक्नोलॉजी पैकेज 2024 में मिला। अगस्त 2023 में कोरवा में बनी पहली राइफल में भारतीय सामग्री की हिस्सेदारी करीब 5 प्रतिशत थी, दिसंबर 2024 में यह 15 प्रतिशत हुई और अगस्त 2026 तक सभी 50 प्रमुख तथा लगभग 180 छोटे कलपुर्जे भारत में बनने लगे।

इस स्वदेशीकरण की असली चुनौती सिर्फ असेंबली नहीं थी। विशेष स्टील मिश्रधातुओं, सिप्रिंग,

इंजीनियरिंग प्लास्टिक, कंपोजिट, कोटिंग और सटीक रासायनिक संरचना वाली धातुओं को भारतीय स्तर पर विकसित करना पड़ा। इसके लिए एडवांस्ड वेपन एंड इस्किपमेंट इंडिया लिमिटेड और अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज समेत भारतीय औद्योगिक साझेदारों ने सत्यापन नेटवर्क तैयार किया। टीमों ने देशभर में करीब 76 सब-वेंडरों का निरीक्षण किया, जिनमें लगभग आधे उत्तर प्रदेश, खासकर कानपुर और लखनऊ क्षेत्र में हैं।

अब कोरवा में करीब 76 तरह के परीक्षण करने वाली अपनी प्रयोगशाला है। हर राइफल को स्वीकार किए जाने से पहले करीब 70 राउंड फायर किए जाते हैं, जिनमें दो हाई-प्रेसर राउंड सामान्य से करीब 50 प्रतिशत अधिक दबाव पैदा करते हैं। पहली पूरी तरह भारतीय एके-203 ने लगातार 3,000 राउंड की फायरिंग परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी की। साथ ही सेना के परीक्षण के लिए 100 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री वाली 10 राइफलें तैयार की जा रही हैं।

बताया जा रहा है कि अब तक करीब 70 हजार राइफलें सेना को दी जा चुकी हैं। अप्रैल 2027 से उत्पादन क्षमता एक राइफल हर 100 सेकंड तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कंपनी को 1.5 लाख से अधिक राइफलों की संभावित मांग के संकेत मिल चुके हैं और आगे नियात तथा कलारिफिकेचन श्रेणी के अन्य हथियारों की दिशा में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

बहरहाल, रणनीतिक संदेश साफ है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि तकनीक को आत्मसात कर अपनी रक्षा औद्योगिक क्षमता खड़ी कर रहा है। एस-400 भारत की दूर से आने वाले हवाई खतरे को रोकने की क्षमता बढ़ाता है, जबकि पूरी तरह स्वदेशी एके-203 युद्ध के सबसे बुनियादी स्तर पर सैनिक की आत्मनिर्भरता मजबूत करता है। यही संयोजन भारत की बदलती सैन्य शक्ति की असली तस्वीर है। यानि आसमान में मजबूत सुरक्षा कवच और जमीन पर भारतीय हाथों से बना ‘शेर’।

नेपाल की त्रासदी से भारत को सबक लेने की जरूरत

ललित गर्ग

नेपाल में 26 अगस्त 2026 को आई विनाशकारी बाढ़ और हिमस्खलन ने एक बार फिर यह कठोर सत्य सामने ला दिया है कि प्रकृति के साथ घिलवाड़ और पहाड़ों की संवेदनशीलता की अनदेखी मानव सभ्यता के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। भोटेकोशी नदी तंत्र में ग्लेशियर के बड़े हिस्से के टूटने, बर्फ-पत्थरों के विशाल मलबे के नीचे आने और नदी के प्रवाह में अस्थायी अवरोध बनने के बाद अचानक बाढ़ का जो रौंद एवं भयावह रूप सामने आया, उसने नेपाल और चीन के तिब्बती क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। 29 अगस्त तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार नेपाल में 579 और तिब्बत में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है तथा लगभग 2,482 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हजारों लोगों को बचाया गया है, लेकिन दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार बने नए खतरे के कारण राहत एवं बचाव कार्य अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। यह घटना केवल नेपाल की प्राकृतिक त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए भविष्य का भयावह संकेत है। प्रारंभिक वैज्ञानिक आकलन बताते हैं कि ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, जिससे बर्फ, चट्टान, मिट्टी और मलबे का विशाल प्रवाह पैदा हुआ। इसने नदी के प्रवाह को अवरूद्ध किया और बाद में जमा पानी तथा मलबे के दबाव से अचानक विनाशकारी बाढ़ आई। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे घटनाक्रम को केवल सामान्य बाढ़ कहना भूल होगी, यह ग्लेशियर, भूस्खलन, मलबा-प्रवाह और नदी-बाढ़ जैसे अनेक खतरों के एक साथ सक्रिय होने वाली ‘बहु-आपदा’ का उदाहरण है।

इस त्रासदी का सबसे बड़ा संदेश जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। हिमालय केवल बर्फ से ढकी पर्वतमाला नहीं, बल्कि एशिया की जल-सुरक्षा का आधार है। तापमान बढ़ने के साथ ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहे हैं और अनेक नई ग्लेशियर झीलें बन रही हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के अनुसार हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में लगभग 25,000 ग्लेशियर झीलें हैं और बढ़ता तापमान ग्लेशियर झीलों के फटने यानी (जीएलओएफ) के जोखिम को बढ़ा रहा है। नेपाल में 1920 के दशक से अब तक 90 से अधिक ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ दर्ज की जा चुकी हैं। इसलिए यह मान लेना उचित नहीं होगा

कि नेपाल की घटना का एकमात्र कारण ग्लोबल वार्मिंग ही है। भूकंपीय गतिविधियां, भूगर्भीय अस्थिरता, अत्यधिक वर्षा, हिमस्खलन और प्राकृतिक ढलानों की कमजोरी भी महत्वपूर्ण कारक हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन इन जोखिमों को बढ़ाने वाली पृष्ठभूमि अवश्य तैयार कर रहा है। गर्म होता हिमालय ग्लेशियरों और पर्वतीय भूभाग को अस्थिर कर रहा है, जिससे ऐसी घटनाओं की संभावना तोत्रता और व्यापकता बढ़ सकती है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर सावधानी बरती है कि किसी एक घटना को सीधे जलवायु परिवर्तन का परिणाम घोषित करने के बजाय दीर्घकालिक जलवायु और भूगर्भीय बदलावों को साथ देखकर समझना चाहिए।

नेपाल की घटना भारत के लिए भी गहरी चेतावनी है। इस चेतावनी से सीख लेने की जरूरत है। उत्तराखंड की केदारनाथ त्रासदी, 2021 की ऋषिगंगा आपदा और हिमालयी राज्यों में बार-बार आने वाली बाढ़, भूस्खलन एवं बादल फटने की घटनाएं पहले ही बता चुकी हैं कि पहाड़ों की सहनशीलता असीमित नहीं है। हिमालय में सड़कें, सुरंगें, जलविद्युत परियोजनाएं, होटल, बस्तियां और अन्य निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के नाम पर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इनके लिए पर्वतीय पर्यावरण की वहन क्षमता का पर्याप्त आकलन हो रहा है?

विकास जरूरी है, मगर ऐसा विकास जो पहाड़ों को खोखला करके ही संभव हो, अंततः मानव जीवन और स्वयं विकास दोनों के लिए संकट बन सकता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता ‘आपदा के बाद राहत’ से आगे बढ़कर ‘आपदा से पहले तैयारी’ की है। अत्याधुनिक सेंडलाइट निगरानी, ड्रोन, रडार, नदी सेंसर, ग्लेशियर और ग्लेशियर झीलों की निरंतर निगरानी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पूर्वानुमान प्रणालियों की हिमालयी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकसित करना होगा। शुरुआती चेतावनी प्रणाली केवल राजधानी या प्रशासनिक केंद्र तक सीमित न रहे, बल्कि पहाड़ के अंतिम गांव तक मोबाइल संदेश, सायरन, रेडियो और स्थानीय स्वयंसेवी तंत्र के माध्यम से पहुंचे। नेपाल में वर्तमान त्रासदी के बाद भी एक और संभावित झील के फटने की आशंका ने स्पष्ट कर दिया है कि एक आपदा समाप्त होते ही दूसरी आपदा का खतरा पैदा हो सकता है।

कांग्रेस विधायक मंडावी के नेतृत्व में तहसीलदार को सौंपा झापन

बीजापुर। जिला मुख्यालय बीजापुर के नगरपालिका क्षेत्र में घरों के राजस्व पट्टे की मांग को लेकर वार्डवासियों ने कांग्रेस पार्टी और विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में नगरपालिका कार्यालय का घेराव किया। वार्ड क्रमांक 1, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वर्षों से घर बनाकर रह रहे लोगों को उनके मकानों का राजस्व पट्टा दिया जाए। वार्डवासियों का आरोप है कि नगरपालिका परिषद बीजापुर की



ओर से समय-समय पर उनके मकानों को तोड़ने और घर खाली करने के

नेटिस दिए जाते हैं। इससे लोगों में भय का माहौल है। उनका कहना है कि

वर्षों से बने घरों को छोड़कर वे आखिर कहां जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान

पट्टे की मांग को लेकर वार्डवासियों का प्रदर्शन

विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा और नगरपालिका अध्यक्ष गीता सोम पुजारी पर निशाना साधा। विधायक ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले भाजपा और नगरपालिका अध्यक्ष ने लोगों को घर और पट्टा देने का वादा किया था, लेकिन अब पट्टा देने के बजाय मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है।

विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी नगरपालिका कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बैरिकेडिंग को पाट कर विधायक

और ग्रामीण नगरपालिका के मुख्य गेट तक पहुंच गए। मौके पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही और प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार बीजापुर को ज्ञापन सौंपकर पट्टा देने और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। ज्योग्राफिकमैप्स और जीपीएस गाइड एक्सप्लोर करना

मामले में तहसीलदार बीजापुर ने बताया कि पट्टे की मांग को लेकर ग्रामीणों का आवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्व भूमि के आबादी क्षेत्र में जिन लोगों का कब्जा है, उन्हें नियमानुसार पट्टा दिया जाना संभव है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि वन विभाग की भूमि पर पट्टा दिया जाना संभव नहीं होगा। अब वार्डवासियों की इस मांग और नगरपालिका क्षेत्र में मकानों को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।

दुर्ग-धमतरी के बाद बलरामपुर में ईडी की दबिश

अपर कलेक्टर चेतन बोरघारिया से पूछताछ जारी



बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। दुर्ग और धमतरी के बाद अब श्वश्र की टीम ने बलरामपुर में दबिश दी है। जांच एजेंसी की टीम दो वाहनों से बलरामपुर पहुंची और सीधे सर्किट हाउस गई, जहां अपर कलेक्टर चेतन बोरघारिया से पूछताछ की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, श्वश्र की टीम सुबह दो वाहनों से बलरामपुर पहुंची। टीम के सर्किट हाउस पहुंचने के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इसके बाद अपर कलेक्टर चेतन बोरघारिया को बुलाकर उनसे पूछताछ शुरू की गई। फिलहाल पूछताछ का सिलसिला जारी है।

चेतन बोरघारिया का पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से भी जुड़ाव रहा है। वे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी के तौर पर काम कर चुके हैं। वर्तमान में वे बलरामपुर में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। ऐसे में श्वश्र की टीम द्वारा उनसे पूछताछ किए जाने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

फिलहाल श्वश्र की इस कार्रवाई का संबंध किस मामले से है, इसे लेकर

आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जांच एजेंसी की ओर से भी पूछताछ के कारण या जांच के दायरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

सर्किट हाउस के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्वश्र की टीम अपनी कार्रवाई कर रही है और पूछताछ के दौरान क्या जानकारी सामने आती है, इसका फिलहाल इंतजार किया जा रहा है।

बलरामपुर में श्वश्र की कार्रवाई से पहले दुर्ग में भी जांच एजेंसी ने दबिश दी थी। पुरानी भिलाई स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पीए के.के. चंद्रवंशी के घर श्वश्र की टीम पहुंची थी। करीब आठ अधिकारियों की टीम दो वाहनों से वहां पहुंची और घर के अंदर दस्तावेजों की जांच की गई। सुरक्षा के लिए जवान भी तैनात किए गए थे। कार्रवाई किस मामले से जुड़ी है, इसकी आधिकारिक जानकारी

सामने नहीं आई है।

इसके अलावा सिकोल भांटा में रियायट पटवारी कमलेश राजूपत के निवास पर भी श्वश्र की टीम पहुंची थी। यहां दुर्ग के बड़े बिल्डर्स से लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई है। कमलेश राजूपत वर्तमान में पटवारी संच के अध्यक्ष हैं, जबकि उनकी बेटी पटवारी के पद पर कार्यरत हैं।

इधर, धमतरी में भी श्वश्र की टीम ने कार्रवाई की। जांच एजेंसी की टीम चेतन बोरघारिया के घर पर जांच कर रही है। करीब छह सदस्यीय टीम दो वाहनों से वहां पहुंची थी और दस्तावेजों समेत अन्य रिकॉर्ड की पड़ताल किए जाने की जानकारी है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बल भी तैनात रहे।

फिलहाल बलरामपुर, दुर्ग और धमतरी में हुई इन कार्रवाइयों को लेकर श्वश्र की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जांच पूरी होने और एजेंसी की ओर से जानकारी जारी किए जाने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इन कार्रवाइयों का दायरा क्या है और जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं।

कोर्ट ने आरोपी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

आरंग। घरेलू विवाद में पत्नी की निर्मम हत्या कर मामले को छिपाने की साजिश रचने वाले आरोपी पति को जिला न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत ने अभियुक्त पर 3,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से मामले की मजबूत पेरवी अपर लोक अभियोजक राहुल गुप्ता ने की। मामला आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम गौरभाट का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 जनवरी 2025 को आरोपी शेखर साहू (44 वर्ष) का अपनी पत्नी दशोदा साहू के साथ विवाद हुआ था। उस समय घर के

अन्य सदस्य रिश्तेदार के यहां गए हुए थे। मौका पाकर शेखर ने रस्सी से गला घोटकर पत्नी की हत्या कर दी। हत्या को हादसा या खुदकुशी साबित करने के लिए आरोपी ने झूठी कहानियां गढ़ीं। उसने परिजनों को बताया कि पत्नी सेप्टिक टैंक के पास चक्कर खाकर गिर गई, तो वहीं रिश्तेदारों से कहा कि उसने साड़ी से फांसी लगा ली। अस्पताल ले जाते वक्त आरोपी लगातार दबाव बनाता रहा और रास्ते में ही एंबुलेंस चालक से मौत की बात कहकर शव घर वापस ले आया। इसके बाद वह जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कराने की फिराक में जुट गया। शव मुक्तिधाम पहुंच चुका था, लेकिन आरोपी की



जल्दबाजी और बयानों में विरोधाभास देखकर परिजनों ने तुरंत आरंग पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही आरंग पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रमेशन घाट पहुंचकर अंतिम संस्कार को रुकवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी एवं विवेचना अधिकारी राजेश सिंह और मर्ग जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार भोई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस का संदेह सही साबित हुआ और खुलासा हुआ कि महिला की मौत गला घोटने से हुई थी।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

नाबालिगों की मदद से हुई बड़ी चोरी का खुलासा आरोपी जेल जांजगीर चांपा।

जांजगीर चांपा के बलौदा में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चोरी के पीछे सबसे बड़ा योगदान नाबालिगों का है। चोरी के मुख्य आरोपियों ने नाबालिगों के मदद से घर के अंदर प्रवेश किया और फिर पूरी वारदात को अंजाम दिया।इस केस में पुलिस ने 3 नाबालिगों को बाल सुधार गृह में भेजा है।वहीं चोरी के सामान खरीदने वाले सोनार सुमित अग्रवाल समेत मुख्य आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। बलौदा पुलिस थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा के मुताबिक बलौदा नगर पंचायत के वार्ड 7 में रहने वाले नवीन सोनी अपने परिवार के साथ घर में सोए थे। सुबह उठने पर कमरे की कुंडी बाहर से बंद मिली। बाद में घर के दूसरे कमरे में जाकर देखा तो आलमारी का ताला टूटा था। आलमारी के लोकर में रखे सोने- चांदी के जेवरात और नकदी चोरी हो चुके थे। इस मामले में थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 386/2026, धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

धमतरी में बच्चों से भरी चलती स्कूल बस में लगी आग

धमतरी। जिले में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक बस में अचानक आग लग गई। घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र के सेहराडबरी गांव के पास की है। बस में उस वक्त करीब 25 स्कूली बच्चे सवार थे। बच्चों के साथ एक शिक्षक, ड्राइवर और हेलपर भी मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ। सड़क से गुजर रहे एक राहगीर की नजर बस से निकल रहे धुएं पर पड़ी। उसने तत्काल ड्राइवर को इसकी जानकारी दी। खतरे को भांपते हुए ड्राइवर ने बिना देर किए बस को सड़क किनारे रोक दिया। बस रुकते ही बच्चों को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान बच्चों और स्कूल स्टाफ में कुछ देर के लिए अफरातफरी की स्थिति बनी रही। हालांकि ड्राइवर और स्कूल स्टाफ की तत्परता से सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना तत्काल डायल 112 और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया।

सीक्रेट चेंबर बनाकर तस्करी, 2.23 करोड़ का गांजा जब्त

कबीरधाम/जगदलपुर। जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चिल्फो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कबीरधाम पुलिस ने कटेनर ट्रक के गुप्त चेंबर से 4 किंटल 47 किलो 445 ग्राम गांजा बरामद किया है। जब गांजे की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 23 लाख 75 हजार 250 रुपये है।पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर कटेनर ट्रक और मोबाइल फोन सहित कुल 2 करोड़ 50 लाख 80 हजार 250 रुपये का सामान जब्त किया है। कबीरधाम एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना चिल्फो पुलिस एनएच-30 पर थाना परिसर के सामने वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बोड़ला की ओर से आ रहे एक कटेनर ट्रक को रोककर जांच की गई।पुलिस ने बताया कि वाहन चालक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पूछताछ और तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ड्राइवर सीट के ऊपर बनाए गए गुप्त चेंबर में खाकी रंग के टेप से लिपटे पैकेट मिले।

गणेश आगमन की तैयारी में जुटे बंगाली मूर्तिकार

बलरामपुर। बलरामपुर जिले में गणपति आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए मूर्तिकार अभी से प्रतिमाओं को आकार देना शुरू कर चुके हैं।रामानुजगंज के आसपास बंगाली मूर्तिकारों के लिए ये समय काफी अहम है।क्योंकि उनके साल भर का खर्च गणपति और दुर्गा पूजन के दौरान बेची गई मूर्तियों से ही निकलता है।इसलिए यहां रहने वाले सभी मूर्तिकार कड़ी मेहनत से प्रतिमाएं बनाते में जुटे हैं।रामानुजगंज के बंगाली मूर्तिकारों की माने तो इस बार पहले की तुलना में गणपति मूर्ति की डिमांड ज्यादा है। लोगों ने पहले से ही ऑर्डर दे डिमा है। ऐसे में मूर्तिकार तय समय से पहले ही काम पूरा करना चाहते हैं।इसलिए दिन रात कड़ी मेहनत करके मूर्ति बनाने में जुट चुके हैं।फिर भी महंगे सामान ने मूर्तिकारों पर असर डाला है।क्योंकि पहले की तुलना में इस बार मूर्ति बनाने में लगने वाला सामान महंगा हो चुका है। इस बार हम यहां गणेश जी की 60-65 मूर्तियां बना रहे हैं हर डिजाइन की मूर्तियां हैं।

8 साल बाद मिला किसान को न्याय एवसी ने सुनाया आदेश

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एनएचआई को 72 डिसमिल भूमि का अधिग्रहण कर प्रार्थी को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। पहली याचिका पर हाईकोर्ट ने निरीक्षण, सीमांकन और मुआवजा प्रक्रिया के लिए 60 दिन की समय-सीमा तय की थी। अनुपालन में देरी के बाद मामला अवमानना तक पहुंचा। अब ताजा आदेश में अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए छह माह की समय-सीमा तय की गई है।बिलासपुर जिले के ग्राम मुंडिपार निवासी किसान मनमोह गोंड ने अपनी जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मुआवजे के लिए किसान ने लगभग आठ वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी। रायपुरःबिलासपुर बायपास के निर्माण से किसान की भूमि प्रभावित हुई थी। जिस जमीन पर कभी गन्ने की फसल लहलहाती थी, वहां अब चमचमती सड़क बन चुकी है।लेकिन भूमि अधिग्रहण के बाद भी प्रभावित किसान को मुआवजा मिलने में देरी हुई। पहली याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए थे।

मकान की नींव की खुदाई में मिलीं प्राचीन मूर्तियां और ब्रिटिशकालीन सिक्के

जांजगीर-चांपा। अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम परसाही बाना में मकान निर्माण के दौरान खुदाई में कुछ प्राचीन मूर्तियां और सिक्के मिलने का मामला सामने आया है। इनमें एक सिक्के पर 1818 अंकित होने की बात सामने आई है। वस्तुएं मिलने की खबर के बाद गांव में इसकी चर्चा शुरू हो गई। सूचना मिलने पर अकलतरा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी वस्तुओं को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया।पुलिस ने अब इन मूर्तियों और सिक्कों की वास्तविकता तथा ऐतिहासिक महत्व की जांच के लिए पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा है। विभाग के विशेषज्ञों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मूर्तियां किस धातु की हैं और सिक्के वास्तव में किस दौर के हैं।जानकारी के अनुसार, ग्राम परसाही बाना निवासी सम्पत कंवर अपने घर में निर्माण कार्य करा रहे थे। मकान की



नींव के लिए खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान सम्पत कंवर ने गांव में बताया कि उन्हें सपना आया था, जिसमें घर की नींव के नीचे सोने की मूर्तियां और पुराने सिक्के दबे होने की बात सामने आई थी। इसके बाद उन्होंने गांव के एक बैगा को बुलाया। बताया जा रहा है कि बैगा ने पूजा-पाठ करने के बाद खुदाई कराई। इसी दौरान कुछ मूर्तियां और पुराने सिक्के मिलने की बात सामने आई। मूर्तियां मिलने के बाद बैगा को आशंका हुई कि ये सोने की हो सकती हैं और इनकी कीमत लाखों रुपये तक हो सकती है। इसी बात को

लेकर मूर्तियों को अपने पास रखने के संबंध में सम्पत कंवर और बैगा के बीच विवाद की स्थिति बन गई। सम्पत कंवर का कहना था कि मूर्तियां उनके घर की जमीन से निकली हैं, इसलिए वे इन्हें अपने पास रखेंगे। दूसरी ओर बैगा भी मूर्तियां लेने की बात पर अड़ा रहा। विवाद बढ़ने के बाद सम्पत कंवर ने मामले को सूचना अकलतरा पुलिस को दी। पुलिस के कब्जे में आई वस्तुओं में कुछ पुराने सिक्के भी बताए जा रहे हैं। इनमें एक सिक्के पर लिखा होने की जानकारी सामने आई है। सिक्के पर 1818 अंकित होने की बात भी कही जा रही है। इसी आधार पर इन्हें ब्रिटिशकालीन सिक्के होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि मूर्तियां वास्तव में सोने की हैं या किसी अन्य धातु से बनी हुई हैं। इसी तरह सिक्के किस धातु के हैं और उनका

वास्तविक ऐतिहासिक महत्व क्या है, यह भी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। अकलतरा थाना प्रभारी जय कुमार साहू ने बताया कि सम्पत कंवर के घर से मिली मूर्तियों और अन्य वस्तुओं को पुलिस ने सुरक्षित अपने कब्जे में रखा है। मामले की जांच के लिए पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा गया है। थाना प्रभारी के मुताबिक, पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ जांच के बाद ही यह स्पष्ट कर पाएंगे कि मूर्तियां किस धातु की हैं, कितनी पुरानी हैं और उनका कोई ऐतिहासिक महत्व क्या नहीं। इसी तरह सिक्कों की जांच से उनके वास्तविक समय और ऐतिहासिक महत्व का भी पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने मिली सभी वस्तुओं को सुरक्षित रखा है। अब पुरातत्व विभाग की जांच रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मकान की नींव की खुदाई से मिली ये वस्तुएं वास्तव में कितनी पुरानी और महत्वपूर्ण हैं।

छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू आउटब्रेक सबसे ज्यादा दुर्ग में खतरा, मरीजों की संख्या बढ़ी

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मरीज लगातार मिल रहे हैं। दुर्ग जिले में भी स्वाइन फ्लू यानी ॥1१॥ संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अकले दुर्ग जिले में अब तक कुल 13 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दुर्ग में अबतक स्वाइन फ्लू के 13 मरीज मिले हैं। इनमें चार मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि दो मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं 7 संक्रमित मरीज अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और उनका उपचार जारी है।महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉ। सी बी एस बंजारे ने बताया कि संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। दुर्ग जिले के सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि ॥1१॥ का कोई पॉजिटिव मरीज सामने आने पर तत्काल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दें। मरीजों के



उपचार के साथ संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। महामारी नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को एच 1 एन 1 संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

नागरिकों से अपील भीडभाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। जरूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल करें।हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोते रहें। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि किसी व्यक्ति को बुखार, खांसी, गले में खराश या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दें, तो लापरवाही न बरतें और तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क कर जांच कराएं।



आयुष, योग और आध्यात्म से आरोग्य की ओर छत्तीसगढ़

लोककल्याण की नई धारा : परंपरा, विज्ञान और जनभागीदारी
के संगम से स्वस्थ छत्तीसगढ़ की ओर

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री



छत्तीसगढ़ आज केवल विकास के पारंपरिक मानकों पर ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, जीवनशैली और समग्र कल्याण के क्षेत्र में भी एक नई पहचान गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में आयुष, योग और आध्यात्म को जन-जन तक पहुंचाने का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी और भारतीय जीवन मूल्यों को आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य सेवाओं का ऐसा मॉडल विकसित किया है, जो उपचार के साथ-साथ निरोगी जीवन की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष ग्राम, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, योगा वेलनेस सेंटर, पंचकर्म सेवाएं, विशेष आयुष कार्यक्रम, औषधीय पौधों का संवर्धन और जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से राज्य ने लाखों लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं। आज छत्तीसगढ़ में आयुष केवल चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और आत्मनिर्भर जीवन का जनआंदोलन बन चुका है।

“

छत्तीसगढ़ की पहचान केवल प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत से नहीं, बल्कि स्वस्थ और जागरूक समाज से भी बनेगी। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का प्रत्येक नागरिक आयुष, योग और भारतीय जीवन मूल्यों से जुड़कर स्वस्थ, निरोग और आत्मनिर्भर जीवन जी सके। आयुष अब केवल परंपरा नहीं, बल्कि आधुनिक शोध और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित वैश्विक समाधान बन चुका है। हमने आयुष सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने, योग को जन-आंदोलन बनाने और आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य संस्कृति को मजबूत करने के लिए अनेक ऐतिहासिक पहल की हैं। आयुष ग्राम, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, योगा वेलनेस सेंटर, विशेष चिकित्सा कार्यक्रम और औषधीय पौधों के संरक्षण जैसे प्रयासों से छत्तीसगढ़ देश में एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहा है।

हमारा संकल्प है - स्वस्थ नागरिक, समृद्ध परिवार और सशक्त छत्तीसगढ़।

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

”

आयुष आधारित स्वास्थ्य क्रांति : गांव से शहर तक पहुंच रही समग्र चिकित्सा



400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का नया स्वरूप

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के संचालन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। राज्य में स्वीकृत सभी 400 आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र पूर्ण रूप से संचालित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य परामर्श, रोग निवारण और जीवनशैली प्रबंधन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन केंद्रों ने ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत किया है और लोगों को बीमारी के उपचार से आगे बढ़कर स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में प्रेरित किया है।



32 योगा वेलनेस सेंटर योग बना जन-जन का स्वास्थ्य साथी

छत्तीसगढ़ में संचालित 32 आयुष योगा वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य जागरूकता के प्रभावी केंद्र बनकर उभरे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक 10.60 लाख से अधिक नागरिकों ने योग, प्राणायाम, ध्यान और प्राकृतिक जीवनशैली का लाभ प्राप्त किया है। प्रशिक्षित योग विशेषज्ञों द्वारा नियमित योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, ध्यान, आहार परामर्श तथा तनाव प्रबंधन संबंधी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। योग अब केवल व्यायाम नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का माध्यम बन चुका है।



146 आयुष ग्राम गांव-गांव में स्वास्थ्य और जागरूकता का अभियान

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राज्य के 146 विकासखंडों में आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। इन गांवों में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, औषधीय पौधों की जानकारी तथा स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनभागीदारी के माध्यम से संचालित यह योजना ग्रामीण जीवनशैली को स्वास्थ्य के साथ जोड़ने का अभिनव प्रयास है। आयुष ग्रामों में लोगों को घरेलू औषधियों, पोषण, योगाभ्यास तथा रोग निवारण संबंधी जानकारी देकर स्वस्थ जीवन की दिशा में प्रेरित किया जा रहा है।



हर्बल स्टेट की पहचान औषधीय संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ को लंबे समय से 'हर्बल स्टेट' के रूप में पहचान प्राप्त है। राज्य में लगभग 1525 प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जो इसे देश के सबसे समृद्ध औषधीय क्षेत्रों में शामिल करते हैं। आयुष विभाग द्वारा अश्वगंधा, शतावरी, कालमेघ, सर्पगंधा, लेमनग्रास, तुलसी, गुडूची, सहजन, गिलोय, एलोवेरा, ब्राह्मी, हल्दी, आंवला, इलायची, मुलेठी और अन्य औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और जैव विविधता को भी मजबूती मिल रही है।

विश्व रिकॉर्ड से विश्व पटल तक : योग में छत्तीसगढ़ की नई पहचान

छत्तीसगढ़ योग आयोग के प्रयासों से राज्य में योग जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। सेतुबंध आसन के सामूहिक प्रदर्शन में 1100 से अधिक योग साधकों की भागीदारी ने राज्य को विश्व रिकॉर्ड दिलाया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग महोत्सव, काउंटडाउन कार्यक्रम और जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से लाखों लोग योग से जुड़ रहे हैं। स्कूलों, महाविद्यालयों, कार्यालयों और ग्राम पंचायतों तक योग की पहुंच ने छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी योग राज्यों में शामिल कर दिया है।



पंचकर्म, चिकित्सा शिविर और जनसेवा : आयुष पहुंचा हर द्वार

आयुष विभाग द्वारा नियमित स्वास्थ्य मेले, हाट-बाजार शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, पंचकर्म चिकित्सा, योग शिविर तथा औषधि वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए मोबाइल चिकित्सा गतिविधियां और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।



कायाकल्प-आयुष : गुणवत्ता और स्वच्छता का राष्ट्रीय मॉडल

स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लागू कायाकल्प-आयुष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ने देशभर में नई मिसाल कायम की है। राज्य ने आयुष संस्थानों के मूल्यांकन और प्रोत्साहन की अभिनव व्यवस्था लागू कर अनेक संस्थानों को पुरस्कृत किया। इस पहल ने आयुष स्वास्थ्य संस्थानों में सेवा गुणवत्ता और जनविश्वास दोनों को मजबूत किया है।



महिला स्वास्थ्य और जनजागरूकता : आयुष का संवेदनशील पक्ष

आयुष ग्रामों और औषधालयों के माध्यम से महिलाओं, किशोरियों, गर्भवती माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविरों में पोषण, एनीमिया नियंत्रण, महिला स्वास्थ्य, योग और स्वच्छता संबंधी परामर्श दिए जा रहे हैं। ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच रही ये सेवाएं स्वास्थ्य के साथ-साथ जागरूकता का भी सशक्त माध्यम बन रही हैं।



चार राष्ट्रीय आयुष कार्यक्रम : जीवन के हर चरण में स्वास्थ्य सुरक्षा



आयुर्विद्या : बच्चों में स्वास्थ्य और संस्कार

स्कूली बच्चों को आयुर्वेद, योग और स्वस्थ जीवनशैली से परिचित कराया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण, योग प्रशिक्षण, औषधीय उद्यान भ्रमण तथा जागरूकता व्याख्यान इसके प्रमुख घटक हैं।



सुप्रजा : मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की सुरक्षा

गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा माताओं को आयुर्वेदिक परामर्श, गर्भ संस्कार, एपनसी एवं पीएनसी सेवाओं के माध्यम से स्वस्थ मातृत्व की दिशा में सहायता प्रदान की जा रही है।



कारुण्य पेलिएटिव केयर : संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा

असाध्य और जीवन-घातक बीमारियों से जुझ रहे रोगियों को घर-घर जाकर उपचार, परामर्श और देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।



ऑस्टियोआर्थराइटिस एवं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कार्यक्रम

जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित रोगों के आयुर्वेदिक उपचार एवं प्रबंधन के माध्यम से हजारों मरीज लाभान्वित हो रहे हैं।

आध्यात्म से आरोग्य :

मानसिक स्वास्थ्य की नई दिशा

आधुनिक जीवनशैली से उत्पन्न तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं के समाधान के लिए योग, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आयुष योगा वेलनेस सेंटरों में ध्यान, प्राणायाम और मानसिक संतुलन पर केंद्रित कार्यक्रम लोगों को स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं।

यह पहल शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी समान महत्व देने की भारतीय परंपरा को पुनर्स्थापित कर रही है।



स्वस्थ, संतुलित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की ओर

आयुष, योग और आध्यात्म के समन्वित प्रयासों ने छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई पहचान प्रदान की है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से लेकर आयुष ग्रामों तक, योगा वेलनेस सेंटरों से लेकर राष्ट्रीय आयुष कार्यक्रमों तक, और औषधीय पौधों के संरक्षण से लेकर जन-जागरूकता अभियानों तक-राज्य ने स्वास्थ्य को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां उपचार से अधिक महत्व स्वास्थ्य संरक्षण को दिया जा रहा है। आयुष, योग और आध्यात्म के माध्यम से स्वस्थ नागरिक, सशक्त समाज और समृद्ध राज्य के निर्माण का यह अभियान आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी स्वास्थ्य मॉडलों में स्थापित करने की क्षमता रखता है।

स्वस्थ छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़

भाजपा का साइलेंट स्ट्राइक, सात दिग्गजों को कमान सौंपकर चौंकाया!

रायपुर। सत्ता में आने के बावजूद आराम फरमाने के बजाय, भाजपा ने इस नई सांगठनिक सर्जरी के जरिए विपक्ष की हर संभावित घेराबंदी को ध्वस्त करने और 2028 के चुनावी समीकरणों को अभी से अपने पक्ष में मोड़ने का अचूक मास्टरप्लान तैयार कर लिया है।

पिछड़ा वर्ग का बड़ा कार्ड बिलासपुर से लखनलाल साहू को कमान: छत्तीसगढ़ की राजनीति में ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) वोट बैंक सबसे निर्णायक माना जाता है, जिसकी आबादी लगभग 45 से 50 प्रतिशत के बीच है। बिलासपुर क्षेत्र के कद्दावर पूर्व सांसद लखनलाल साहू को पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपकर भाजपा ने अपने सबसे बड़े वोट बैंक को सहेजने का दांव खेला है। लखनलाल साहू की साहू समाज और संपूर्ण ओबीसी वर्ग में मजबूत पकड़ है, जिससे भाजपा न केवल बिलासपुर और आसपास के इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत रखेगी, बल्कि विपक्ष के जातिगत जंगणना वाले नैरेटिव की हवा भी निकालेगी।



कृषि प्रधान प्रदेश का दारोमदारः छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता गाँवों और खेतों से होकर गुजरता है। धमतरी-रायपुर क्षेत्र के कुशल रणनीतिकार पूनम चंद्राकर को किसान मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व मंत्री पूनम चंद्राकर की ग्रामीण क्षमताएं और क्षेत्र में गहरी पैठ है। साय सरकार की धान खरीदी, प्रति एकड़ 3100 रुपये मूल्य और कृषक उन्नति योजना जैसे फैसलों को सीधे किसानों के घर तक पहुंचाने का जिम्मा इनके कंधों पर होगा। यह नियुक्ति कांग्रेस के किसान केंद्रित अभियानों को बेअसर करने के लिए काफी अहम मानी जा रही है। पूनम चंद्राकर भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। वे कुर्मी समाज से हैं।

युवाओं को साधने का आक्रामक प्लानः दुर्ग-भिलाई से वैभव बैसः राज्य

की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी युवाओं की है। दुर्ग संभाग के ऊर्जावान नेता वैभव बैस को भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान सौंपकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह सड़कों पर आक्रामकता और सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देगी। वैभव बैस लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और युवाओं, कॉलेज छात्रों व रोजगार के मुद्दों पर उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। वैभव बैस पिछड़े वर्ग से आते हैं। वे कुर्मी समाज से हैं।

महतारी वंदन का सुरक्षा चक्रः रायपुर के वरिष्ठ नेता सुभाष तिवारी: भाजपा की सत्ता वापसी में %महतारी वंदन योजना सबसे बड़ा गेमचेंजर साबित हुई थी। रायपुर से आने वाले वरिष्ठ और अनुभवी नेता सुभाष तिवारी को महिला मोर्चा का प्रभारी बनाकर भाजपा ने अपने इस सबसे मजबूत वोट बैंक को सहेजने की जिम्मेदारी दी है। सुभाष तिवारी का विस्तृत सांगठनिक अनुभव महिलाओं से जुड़े अभियानों को गति देने और इस वर्ग के साथ सीधा संवाद कायम रखने में मदद करेगा।

आदिवासी समीकरणः जगदलपुर से शिरिष अग्रवाल: छत्तीसगढ़ में 31 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति (अजजा) वर्ग की है। जगदलपुर (बस्तर) से आने वाले शिरिष अग्रवाल को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव (बस्तर) और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (सरगुजा) के बाद बस्तर के ही शिरिष अग्रवाल को यह जिम्मा सौंपकर भाजपा ने आदिवासी बहुल संभागों में अपनी मजबूत बढ़त को स्थायी बनाने का काम किया है।

छत्तीसगढ़ की 10 अनुसूचित जाति (अजा) आरक्षित सीटों पर हमेशा कांटे की ठक्कर देखने को मिलती है। मैदानी क्षेत्र और धमतरी-रायपुर प्रभाव वाले डॉ. गुलाब टिकरिहा को अनुसूचित जाति मोर्चा की कमान दी गई है। सतनामी समाज और एससी वर्ग के भीतर भाजपा का प्रभाव बढ़ाने तथा पार्टी की नीतियों को जमीनी स्तर पर उतारने में डॉ. टिकरिहा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी।

सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम जारी, 608 अभ्यर्थी

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में कुल 608 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों को अब साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया 21 सितंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है।



अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित किया गया है।

साक्षात्कार से पहले होगा दस्तावेज सत्यापन: आयोग के अनुसार राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का साक्षात्कार 21 सितंबर 2026 से शुरू हो सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से एक दिन पहले दस्तावेज सत्यापन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराएंगे, उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग जल्द ही साक्षात्कार की विस्तृत समय-सारणी, प्रक्रिया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा। चर्चे तो में इसका मुखपृष्ठ के लिए छोटा और ज्यादा प्रभावी शीर्षक-उपशीर्षक वाला संस्करण भी बना सकता हूं।

प्रदेश की 20 अलग-अलग सेवाओं में कुल 265 पदों पर भर्ती की जानी है।भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 3,921 अभ्यर्थी सफल हुए थे। जून में हुई थी मुख्य परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में सफल 3,921 अभ्यर्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में शामिल होने का अवसर मिला। मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन 6, 7, 8 और 9 जून 2026 को किया गया था। परीक्षा के परिणाम में 608

सेवानिवृत्ति तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है: श्रीवास्तव

■ नागरिक आपूर्ति निगम में श्रीमती इंद्राणी यदु, कनिष्ठ सहायक को भावभीनी विदाई

रायपुर। नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय नवा रायपुर में पदस्थ श्रीमती इंद्राणी यदु, कनिष्ठ सहायक को सेवानिवृत्ति के अवसर पर आज सायं भावभीनी विदाई दी गई। निगम अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने श्रीमती इंद्राणी यदु को शाल, श्रीफल एवं मोमेन्टो देकर सम्मानित किया। निगम कि ओर से उन्हे स्मृति चिन्ह एवं उपहार भेंट के साथ ही अवकाश नगदीकरण एवं जीएसएलआई की राशि का चेक प्रदान किया गया।

समारोह को संबोधित करते हुए संजय श्रीवास्तव ने कहा कि सेवानिवृत्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण



पड़ाव है। यह केवल शासकीय सेवा का समापन नहीं, बल्कि वर्षों की निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से अर्जित अनुभवों की नई यात्रा का प्रारंभ भी है। कार्यक्रम में निगम मुख्यालय के भोसकर विलास सिंघानन प्रबंध संचालक, राजेश सिसोदिया, कार्यपालन संचालक वित्त, दिनेश कुमार नाग, महाप्रबंधक, (प्रशासन) रविन्द्र जैन, उप संचालक (वित्त) महेंद्र साहू,

एस.बी. खापर्डे, ज्योति सोनी, मनोज वर्मा, जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, जी.एच. त्रिनाथ रेड्डी, प्रज्ञा कदम, जसबीर सिंह मकड़, नंदकिशोर मिश्रा, यू सुदर्शन श्रीमती अनामिका वर्मा, श्रीमती दीप्ती केशरवानी अनित वर्मा, विकास वर्मा, रविन्द्र सुखदेवे, बालमिकी साहू, मनहरण यादव, केशव साहू, पुनितराम ध्रुव, एवं निगम मुख्यालय के सभी कर्मियों की सहभागिता रही।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की चुनौतियों पर वैचारिक विमर्श एवं काव्य गोष्ठी

रायपुर। नव छत्तीसगढ़ साहित्य सांस्कृतिक संस्थान रायपुर के तत्वावधान में सोमवार को रायपुर स्थित वृंदावन सभागार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की चुनौतियाँ विषय पर वैचारिक विमर्श एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि, लेखक एवं स्तंभकार संजीव कुमार ठाकुर ने की। मुख्य अतिथि बेंगलुरु से विशेष रूप से पधारे आयोवर्त के प्रबंध संपादक बिजय कुमार सिंह थे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉ. महेंद्र कुमार ठाकुर, व्यंगकार, ज्योतिष, उपसंचालक जनसंपर्क सौरभ शर्मा, पत्रकारिता महाविद्यालय के प्राचार्य देवाशीष मुखर्जी एवं कवि सुरेंद्र रावल छत्तीसगढ़ी कवि-गीतकार मीर अली मीर रहे।कार्यक्रम में अतिथियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के बढ़ते प्रभाव, इसकी संभावनाओं तथा भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त किए। संस्थान के अध्यक्ष डॉ. संजीव ठाकुर ने कहा, एआई विकास की नई दिशा और चुनौतियों की नई राह है। इससे घबराते की जगह इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की आवश्यकता मशीन बुद्धिमान हो सकती है पर मानवीय संवेदनाएं और मानव मस्तिष्क का विकल्प नहीं हो सकती विमर्श के दौरान साहित्य, तकनीक और समसामयिक चुनौतियों को लेकर सार्थक चर्चा हुई। साहित्यकारों एवं कवियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सकारात्मक उपयोग के साथ-साथ इससे जुड़ी चुनौतियों और मानवीय मूल्यों पर भी अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि तकनीकी विकास के साथ मानवीय संवेदनाओं और रचनात्मकता को बनाए रखना आवश्यक है।

प्रदेश में यूसीसी पर व्यापक मंथन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता का सर्वसमावेशी प्रारूप तैयार करने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आज यूसीसी समिति के समक्ष बस्तर से लेकर सरगुजा तक के प्रतिनिधियों की आवाज गूँजी। इस परिचर्चा में सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग और अध्यक्ष राज्य फिल्म विकास निगम ने विवाह, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे संवेदनशील विषयों पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे। समिति के सदस्यों सेवानिवृत्त आईएसएस एम. के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार, सेवानिवृत्त श्रीमती ज्योति राठी सिंह और सदस्य सचिव श्याम धावड़े ने सभी सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्चस्त किया कि राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और



सामाजिक ताने-बाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा।इस दौरान कंवर, गोंड, बैगा और उरांव जैसी प्रमुख जनजातियों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखते हुए आदिवासियों की सदियों पुरानी रूढ़िगत प्रथाओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विशिष्टता को नए कानून में पूर्ण संरक्षण देने की बात कही। इसके साथ ही विवाह पंजीयन, संपत्ति के अधिकार और लिंव-इन रिलेशनशिप जैसे व्यावहारिक मुद्दों पर भी समिति के साथ गंभीर विचार-विमर्श हुआ। महिला अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने जनजातीय परंपराओं के

संरक्षण के साथ-साथ सकारात्मक सामाजिक बदलावों का समर्थन किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार, राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने और धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के संदर्भ में यूसीसी की आवश्यकता को रेखांकित किया। वहीं, राज्य फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक-कला और जनजातीय धरोहर को अक्षुण्ण रखने का सुझाव देते हुए कहा कि वैवाहिक और संपत्ति अधिकारों में समानता से समाज के अंतिम छोर पर खड़ी महिलाओं को नया आत्मविश्वास और कानूनी सुरक्षा मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के संसाधनों की सरेआम लूट: दीपक बैज

रायपुर। नवा रायपुर में आयोजित क्रिटिकल एवं स्टेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी के रोड शो को चंद पूंजीपतियों के दबाव में छत्तीसगढ़ के संसाधनों की लूट की गति बढ़ाने और बांकी बचे खनिजों को लुटाने की कवायद करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र व राज्य सरकारें क्रिटिकल खनिजों जैसे लिथियम, नीकल, क्रोमियम, ग्रेफाइट आदि की खुली नीलामी के नाम पर बड़े निजी और कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने का षडयंत्र कर रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बिना चर्चा के संसद में हाल ही में पारित एमएसडीआर संशोधन अधिनियम के जरिए राज्य के खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर, सेस या लेवी लगाने के अधिकार सीमित किए गए हैं, नीलामी का रोड शो उन्हीं कॉर्पोरेट परस्त्त नीतियों का हिस्सा है, इससे छत्तीसगढ़ जैसे समृद्ध राज्य के राजस्व को भी नुकसान होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने तमनार की जमीन, जंगलों और जल-जंगल-जमीन पर निर्भर आदिवासियों के अधिकारों को कुचलकर कॉर्पोरेट मुनाफे को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2015 में जब पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई थी।

रायपुर कमिश्नरेट में कोई सुरक्षित नहीं : शुक्ला

रायपुर। राजधानी में रोज हो रही हत्यायें चिंताजनक है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रायपुर कमिश्नरेट सहित प्रदेश में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। किसकी कब कहाँ हत्या हो जाये कहा नहीं जा सकता है। बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था के कारण रायपुर शहर तो आदमियों की कलिंगाह बन चुका है। रायपुर में आदमी गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं न सरकार को कोई चिंता है और न ही पुलिस को पुलिस केवल अपराध के आंकड़ो का झुठलाने और गुहमंत्रों कोरी बयान बाजी में लगे है। तीन साल पहले शांत और सुरक्षित राजधानी में 25 दिन में 16 मर्डर हो गये तथा पिछले 4 दिनों में गैंगवार के कारण 2 हत्याएं हो गयी। सरकार और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई। कुछ दिन पहले राजधानी में महिला को रास्ते में रोक कर हत्या कर दी गई उसके बाद उसके शव के साथ दुष्कर्म हो गया। पिछले हफ्ते एक महिला के साथ एक दिन में दो बार गैंग रैप हो गया। राजनांदगांव के चिखली में एक व्यक्ति की घर में घुस कर हत्या हो गई। रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है।प्रदेश में हर दिन 6 हत्या, 8 बालात्कार की घटना हो रही है। सक्ती में एक युवती को उसके घर में घुसकर गोली मार दी गयी।

मरार समाज के उत्थान के लिए समन्वित प्रयास होंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता कृषि एवं उद्यानिकी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े गरीब, पिछड़े, लघु और सीमांत किसानों तक पहुंचाना है। इसके लिए कृषि एवं संबद्ध विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए कहा कि यही शाकम्भरी बोर्ड के गठन का मूल उद्देश्य है। नवा रायपुर स्थित उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय में सोमवार को आयोजित "छत्तीसगढ़ राज्य शाकम्भरी बोर्ड के संचालक मंडल की पहली बैठक" को संबोधित करते हुए श्री नायक ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी क्षेत्र में मरार समाज का योगदान ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। भले ही शाकम्भरी बोर्ड का गठन मरार-पटेल समाज के उत्थान के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन बोर्ड की सोच सभी किसानों के हित और समृद्धि से जुड़ी है। कृषि, उद्यानिकी, जल संसाधन, ऊर्जा, वाणिज्य एवं उद्योग तथा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के समन्वित प्रयासों से किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी।

बिलासपुर-उत्तरी बाईपास की राह में 8 गांवों की जमीन पर लगी रोक

बिलासपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर प्रस्तावित बिलासपुर-उत्तरी बाईपास को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 4-लेन बाईपास के लिए चिन्हित एलाइनमेंट क्षेत्र में आने वाली जमीन के ऋय-विक्रय और विभाजन पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध अंतिम भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगा।प्रशासन के मुताबिक प्रस्तावित बाईपास का निर्माण किलोमीटर 0.000 से 20.921 तक किया जाना है। इस परियोजना के एलाइनमेंट में आने वाले बिलासपुर जिले के सेंदरी, रमतला, बिकोना, नगोई, बिजोर, मोपका, दोमुहानी और ढेंका गांवों की जमीन शामिल है। इन आठ गांवों के कुल 644 खसरों पर यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से परियोजना के अंतिम के संभावित अवैध या अनाधिकृत लेन-देन को रोकने के लिए प्रशासन से कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। इसी के बाद कलेक्टर ने जमीन के हस्तांतरण और विभाजन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।प्रशासन का कहना है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान जमीन की खरीद-बिक्री, बंटोकन या छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजन होने से परियोजना की लागत बढ़ सकती है। साथ ही मुआवजा और स्वाभिव्यक्त संबंधी प्रक्रिया भी जटिल हो सकती है।

पीढियों की धरोहर को मिली कानूनी मुहर

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध कृषि जैव-विविधता और पारंपरिक ज्ञान को एक बड़ी राष्ट्रीय पहचान मिली है। धमतरी जिले के नगरी विकासखंड स्थित ग्राम गुहनालाला के किसान बंसी लाल सोरी द्वारा पीढियों से सहेजे गए पारंपरिक 'चिरपोटी टमाटर' को 'पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण' के तहत आधिकारिक तौर पर पंजीकृत कर लिया गया है। इस उपलब्धि पर कलेक्टर ने बंसी लाल सोरी को शॉल व पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। 'चिरपोटी टमाटर' के संरक्षण की यह कहानी बंसी लाल के स्वर्गीय पिता मंगलू राम सोरी से शुरू होती है, जो वर्षों तक इस स्थानीय किस्म के बीजों को सहेजकर खेती करते रहे। पिता के निधन के बाद बंसी लाल ने इस पारंपरिक कृषि विरासत को संभाला और बीज संरक्षण के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाया। कृषि विज्ञान केंद्र , धमतरी और प्रभाी के तकनीकी सहयोग से इस किस्म के दस्तावेजीकरण और पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की गई। कलेक्टर के अनुसार, यह पंजीयन केवल एक फसल की पहचान नहीं, बल्कि किसानों के पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय जैव-विविधता के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। के तहत मिले इस अधिकार से किसानों को रिकॉग्निशन एंड रिवॉई जैसी व्यवस्थाओं के तहत प्रोत्साहन मिलने का मार्ग भी प्रशस्त होता है।

तीन दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन का शुभारंभ

रंग-तरंग’ में गूंजे छत्तीसगढ़ के लोकवाद्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंगीत परंपरा, पारंपरिक वाद्ययंत्रों और आधुनिक संगीत के सुरों को एक मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आयोजित तीन दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन 'रंग-तरंग' का मंगलवार को महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में लोकवाद्यों की गूंज, शास्त्रीय वाद्ययंत्रों की मधुर धुनों और लोकगायन की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया।

‘रंग-तरंग’ का आयोजन 1 से 3 सितंबर 2026 तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की लोक एवं वाद्य संगीत परंपरा को संरक्षित करने, नई



पीढ़ी तक पहुंचाने तथा लोक एवं वाद्य संगीत से जुड़े कलाकारों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है।

सजी सुरों की महफिल

आयोजन के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न वाद्य एवं संगीत प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोक वादन (पयूजन) की प्रस्तुति श्री विवेकानंद भारती एवं साथियों ने दी।

पियाणो वादन में मोहम्मद अयान रायकर, तबला वादन में नासिर खान, अंबिकापुर, बांसुरी वादन में श्री तारकेश्वर वर्मा, रायपुर तथा लोक गायन में राहुल ठाकुर, रायपुर ने अपनी प्रस्तुतियों से सुरों की मनमोहक छटा बिखेरी। लोकधुनों और पारंपरिक वाद्यों के साथ आधुनिक संगीत के सुरों का संगम कार्यक्रम की खासियत रहा। प्रस्तुतियों में छत्तीसगढ़ की

लोकसंस्कृति की सहजता और विविधता के साथ संगीत के नए प्रयोगों की झलक भी देखने को मिली।

परंपरा और आधुनिकता का संगम जरूरी : कन्नौजे

संस्कृति एवं पुरातत्व संचालक डॉ. संजय कन्नौजे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध लोकसंस्कृति और संगीत परंपरा से है। यहां के पारंपरिक वाद्ययंत्र केवल दर्शकों के मन नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक पहचान और लोकजीवन की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि 'रंग-तरंग' के माध्यम से पारंपरिक लोकवाद्यों और लोकधुनों को आधुनिक संगीत के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे नई पीढ़ी को अपनी

सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ ही कलाकारों को व्यापक पहचान दिलाने में मदद मिलेगी। डॉ. कन्नौजे ने कहा कि वाद्य एवं संगीत कलाकारों के लिए ऐसे मंच उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिलने से कलाकारों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें व्यापक स्तर पर प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। विभाग का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ की लोक एवं वाद्य संगीत परंपरा से जुड़े कलाकारों को निरंतर प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें नए मंच उपलब्ध कराए जाएं।लोकधुनों और पारंपरिक वाद्यों को नए संगीत प्रयोगों के साथ प्रस्तुत करने से युवा पीढ़ी भी सहज रूप से इनसे जुड़ सकती है।

डीएमएफ घोटाला: हाईकोर्ट ने कुर्क संपत्तियों के बदले 4.36 करोड़ की एफडी देने की याचिका खारिज की

रायपुर हाईकोर्ट ने ऋधभ सोनी और उनकी पत्नी कोमल सोनी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क की गई छह अचल संपत्तियों के स्थान पर 4.36 करोड़ रुपये की सार्वधिक जमा स्वीकार करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई वैधानिक या कानूनी अधिकार साबित नहीं कर सके, जिसके आधार पर संपत्तियों के बदले एफडी स्वीकार करने का निर्देश दिया जा सके। अदालत ने



कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम और इसके तहत बनाए गए 2013 के नियमों में सामान्य तौर पर कुर्क अचल संपत्तियों को एफडी से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान नहीं है। केवल नियम 5(5) के तहत कुछ सीमित परिस्थितियों में ही ऐसी अनुमति दी जा सकती है। जिला खनिज कोष में अनियमितताओं से जुड़े कथित अपराध की आय के समतुल्य मूल्य के रूप में ईडी द्वारा 9 दिसंबर, 2024 को

संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया था। इसके बाद 23 मई 2025 को निर्णायक प्राधिकरण द्वारा इस कुर्क की पुष्टि की गई। याचिकाकर्ताओं ने अपील की, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष पुष्टि को चुनौती दी थी और उन अपीलों के लॉबित रहने के दौरान छह संपत्तियों के प्रतिस्थापन की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया कि वे समान मूल्य की एक तरल सार्वधिक जमा राशि उपलब्ध कराने के लिए तैयार थे और संपत्तियों को केवल समतुल्य मूल्य के आधार पर जब्त किया गया था, न कि अपराध की प्रत्यक्ष आय के रूप में।